CNEWS सिटी चीफ

# सिटी चीफ

वर्ष-15, अंक-295
पृष्ठ-8 मूल्य 2 रूपया

महानता कभी ना गिरने में नहीं है, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है.

CITYCHIEFSENDMENEWS@GMAIL.COM

इंदौर, गुरुवार 30 जनवरी 2025

सम्पूर्ण भारत मे चर्चित हिन्दी अखबार

स्थानांतरण नीति (संशोधन)2025

## मप्र में मंत्रियों को तबादले का अधिकार, आदेश जारी

**भोपाल।** मध्यप्रदेश में अभी राज्य और जिला स्तर पर स्थानांतरण पर प्रतिबंध है। शासन ने 24 जून 2021 को राज्य एवं जिला स्तर पर ट्रांसफर नीति जारी की थी। सरकार ने कार्य की सुविधा से उपरोक्त नीति की कण्डिका 9 में संशोधन किया है। इसमें विभाग के मंत्री विशेष परिस्थिति में ट्रांसफर कर सकेंगे। बुधवार को सामन्य प्रशासन विभाग की तरफ से स्थानांतरण नीति (संशोधन)2025 जारी कर दी गई। बता दें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षा में महेश्वर में हुई कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई थी। वहीं, मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त उच्च प्राथमिकता के प्रकरणों में सचिव प्राशसकीय अनुमोदन प्राप्त कर आदेश जारी कर सकेंगे। साथ ही ऐसे ट्रांसफर प्रकरण जिनको करने में विभाग नीति के अनुरूप नहीं पाता है तो ऐसे प्रकरण विभागीय सचिव, विभागीय मंत्री के अनुमोदन के बाद कारण समेत अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय को दोबारा प्रस्तुत कर अग्रिम आदेश प्राप्त करेंगे। इसके अलावा ट्रांसफर नीति के तहत ट्रांसफर करते हुए यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जिस स्थान से ट्रांसफर किया जा रहा है, उस स्थान पर रिक्त पदों का प्रतिशत ट्रांसफर किए जा रहे स्थान से अधिक तो नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग ने कुछ शर्तों के तहत शासकीय कर्मचारियों के ट्रांसफर (स्थानांतरण) के लिए एक नीति जारी की है। इस नीति के अनुसार, सामान्य रूप से ट्रांसफर केवल विशेष परिस्थितियों में ही किए जा सकते हैं। इन परिस्थितियों में शामिल हैं- स्वास्थ्य कारण- जैसे गंभीर बीमारियां (कैंसर, लकवा, दिल का दौरा आदि) के कारण तत्काल स्थानांतरण की आवश्यकता हो। न्यायालय के आदेश- यदि किसी न्यायालय का आदेश हो और उस आदेश का पालन करना आवश्यक हो, लेकिन स्थानांतरण के दौरान कर्मचारी पर कोई विभागीय कार्रवाई लंबित न हो। गंभीर शिकायत या अनियमितता- यदि शासकीय कर्मचारी के खिलाफ गंभीर शिकायत या लापरवाही हो और विभाग ने उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की हो। आपसी अपराध मामला- यदि लोकायुक्त या पुलिस ने कर्मचारी के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया हो और जांच में कोई रुकावट न हो, तो इस कारण भी स्थानांतरण किया जा सकता है। रिक्त पदों की पूर्ति- यदि किसी कर्मचारी के निलंबन, त्यागपत्र, सेवानिवृत्ति या मृत्यु के कारण पद खाली हो और विभाग को लगे कि उस पद को भरना जरूरी है, तो भी स्थानांतरण किया जा सकता है।

## महात्मा गांधी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं

### वह भारत की आत्मा हैं : राहुल गांधी

**नई दिल्ली।** कांग्रेस ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर बृहस्पतिवार को उन्हें श्रद्धांजलि दी और आरोप लगाया कि आज ऐसे लोग हैं जो खुद की ब्रांडिंग के लिए राष्ट्रपिता के चश्मे और लाठी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देश भर में गांधीवादी संस्थानों को नष्ट कर रहे हैं। नाथूराम गोडसे ने 1948 में आज ही के दिन बापू की गोली मारकर हत्या कर दी थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स। पर पोस्ट किया, ।सत्य, अहिंसा, सर्वोदय और सर्वधर्म समभाव के बापू के विचार आज भी हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। हमें उन लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए जो सभी के लिए समानता और उत्थान के उनके आदर्शों को नष्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कहा, आइए, भारत की विविधता में एकता की रक्षा करें और सभी के लिए न्याय और समानता सुनिश्चित करें।। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि महात्मा गांधी सिर्फ एक व्यक्ति नहीं हैं, वह भारत की आत्मा हैं, और हर भारतीय में आज भी जीवित हैं। उन्होंने 'एक्स। पर पोस्ट किया, ।सत्य, अहिंसा और निडरता की शक्ति बड़े से बड़े साम्रा।य की जड़ें हिला सकती है पूरा विश्व बापू के इन आदर्शों से प्रेरणा लेता है। राष्ट्रपिता, महात्मा, हमारे बापू को उनके शहीद दिवस पर शत-शत नमन खरगे और राहुल ने गांधी स्मृति पहुंचकर राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने 'एक्स। पर पोस्ट किया, ।आज से 77 साल पहले महात्मा गांधी की हत्या की गई थी। नाथूराम गोडसे वह व्यक्ति था जिसने बापू पर गोलियां दागी थीं, लेकिन वास्तव में वह एक विचारधारा थी और ऐसे विचारक थे जिन्होंने वह विषैला वातावरण तैयार किया था जिसने राष्ट्रपिता की जान ली।। उन्होंने दावा किया कि आज सत्ताधारी दल में ऐसे सांसद हैं जिनसे गांधी जी और गोडसे में से किसी एक को चुनने को कहा जाता है तो वे कहते हैं कि उन्हें सोचना होगा। रमेश ने कहा, ।आज, सत्ता के शीर्ष पर जो लोग बैठे हैं वे गांधी जी के बलिदान को नहीं मानते और कहते हैं कि भारत को आज़ादी 22 जनवरी 2024 को मिली। आज सत्ता में प्रभावशाली पदों पर बैठे ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने गांधी जी का उसी तरह मज़ाक उड़ाया है, जैसे उन्होंने डॉ. भीमराव आंबेडकर का मजाक उड़ाया था। उन्होंने आरोप लगाया, आज ऐसे लोग हैं जो खुद की ब्रांडिंग के लिए गांधीजी के चश्मे और लाठी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन देश भर में गांधीवादी संस्थानों को नष्ट कर रहे हैं। रमेश ने कहा कि महात्मा गांधी की विरासत की रक्षा, संरक्षण और प्रचार-प्रसार करना बेहद ज़रूरी है तथा आइडिया ऑफ इंडिया का अस्तित्व इसी पर निर्भर है।

## इसरो का 100वां लॉन्च मिशन सफल एनवीएस-02 उपग्रह कक्षा में स्थापित

**श्रीहरिकोटा ।** भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का 100वां लॉन्च मिशन सफल हो गया है। एनवीएस-02 उपग्रह को सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापित करने के बाद इसरो की इस उपलब्धि को बड़ा मुकाम करार दिया जा रहा है। इसरो ने बुधवार सुबह 6.23 बजे अपना 100वां मिशन लॉन्च किया। इसके तहत श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से जीएसएलवी-एफ15 के जरिए 2250 किलोग्राम की नैविगेशन सैटेलाइट एनवीएस-02 को भेजा गया। नैविगेशन उपग्रह एनवीएस-2 नैविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन यानी नाविक शृंखला का दूसरा उपग्रह है। इस शृंखला में कुल पांच सैटेलाइट भेजी जानी हैं। इससे पहले एनवीएस-01, जो दूसरी पीढ़ी का पहला सैटेलाइट था, 29 मई 2023 को जीएसएलवी-एफ12 के जरिए लॉन्च किया गया था। जबकि, एनवीएस-02, एनवीएस सीरीज का दूसरा सैटेलाइट है। इसमें एल1, एल5 और एस बैंड में नेविगेशन पेलोड के साथ-साथ सी-बैंड में रेंजिंग पेलोड भी लगाया गया है, जैसा कि इसकी पहली पीढ़ी की सैटेलाइट एनवीएस-01 में था। अंतरिक्ष मामलों के विशेषज्ञों के मुताबिक, एनवीएस-02 के जरिए भारत अपने नाविक सिस्टम को मजबूत करेगा। इसरो का यह उपग्रह पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से देश में ही बना है। इसे यूआर सैटेलाइट सेंटर (यूआरएससी) में डिजाइन, विकसित और तैयार किया गया है। नवंबर-दिसंबर 2024 के बीच इस सैटेलाइट की टेस्टिंग की गई, जिसमें इसकी हर परिस्थिति का सामना करने की काबिलियत को परखा गया। इसमें भारत के सटीक समय की जानकारी देने के लिए एक परमाणु घड़ी भी लगाई गई है, जिसे रूबिडियम एटॉमिक फ्रीक्वेंसी स्टैंडर्ड (आरएएफएस) भी कहा जाता है।

## अब नहीं बच पाएंगे ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले!

**ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के लिए अब चालान से बचना मुश्किल होने वाला है। सड़क परिवहन मंत्रालय वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र और ड्राइविंग लाइसेंस को आधार से जोड़ने की योजना बना रहा है। इस कदम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वाहन मालिकों और ड्राइवरों की सही जानकारी दर्ज हो और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई हो सके। क्यों आ रहा है नया नियम? मंत्रालय इस बदलाव को मोटर वाहन अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों का हिस्सा बनाने पर विचार कर रहा है। कई वाहन मालिक ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के बाद अपना मोबाइल नंबर या पता बदल लेते हैं, जिससे उन पर जुर्माना लगाना मुश्किल हो जाता है। नए नियम लागू होने के बाद, ऋष्ट और छ्ररुको आधार से लिंक करना अनिवार्य होगा, जिससे चालान और जुर्माने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जा सकेगा। 12,000 करोड़ रुपये के लंबित चालान केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, अब तक 12,000 करोड़ रुपये से अधिक के ई-चालान बकाया हैं। मौजूदा डेटाबेस में वाहन मालिकों के सही पते और मोबाइल नंबर अपडेट न होने के कारण परिवहन विभाग को यह रकम वसूलने में दिक्कत हो रही है। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार अब वाहन और लाइसेंस धारकों की जानकारी को आधार से लिंक करने की योजना बना रही है। परिवहन विभाग के डेटाबेस में दशकों पुराने ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण दर्ज हैं, जिनमें से कई में मोबाइल नंबर, आधार लिंक या अपडेटेड पते की जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में वाहन मालिकों को जल्द ही अपना डेटा अपडेट करवाना पड़ सकता है। यदि किसी वाहन मालिक का चालान बकाया रहता है, तो आधार लिंक होने के बाद एजेंसियों को पता चल जाएगा कि उससे संपर्क कैसे किया जाए। यदि निश्चित समय तक जुर्माना अदा नहीं किया जाता, तो संबंधित व्यक्ति का ऋष्ट या छ्ररु निलंबित, अमान्य या रद्द किया जा सकता है। सरकार के इस कदम से ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित होगा और ई-चालान का भुगतान टालने वालों पर लगाम लगेगी। वाहन मालिकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने ऋष्ट और छ्ररु से जुड़ी जानकारी को जल्द से जल्द अपडेट करवाएं ताकि किसी भी असुविधा से बचा जा सके।**

## टीचर ने 8वीं की छात्रा को बेरहमी से पीटा, आईसीयू में कराना पड़ा भर्ती

**अशोकनगर।** मध्यप्रदेश के अशोकनगर से 8वीं की छात्रा को बुरी तरह पीटने का मामला सामने आया है। यहां एक निजी स्कूल के महिला टीचर ने बच्ची को महज नोटबुक ना लाने के कारण इतना पीट दिया कि उसे आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा। परिजनों ने मामले की शिकायत देहात थाने में की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। परिजनों द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद डीईओ और डीपीसी भी मौके पर पहुंच गए।

जिस स्कूल में शिक्षिका द्वारा छात्रा के साथ मारपीट की गई है उस स्कूल की मान्यता कलेक्टर द्वारा पहले ही रद्द की गई थी। इसके बावजूद स्कूल संचालित हो रहा है। दरअसल अशोकनगर के थूबोन रोड पर भारतीयम पब्लिक स्कूल स्थित है। यहां पढ़ने वाली कक्षा 8 की छात्रा खुशबू केवट को नोटबुक न लाने की बात पर शिक्षिका परी शर्मा ने इतनी बेरहमी से पीटा कि छात्रा बेहोश हो गई। बाद में छात्रा को परिजनों द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां आई सी यू वार्ड में उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि पिटाई से छात्रा की स्मरण शक्ति कमजोर हो गई है। छात्रा से पिटाई के मामले की परिजनों द्वारा उसकी शिकायत देहात थाने में भी की गई है। वहीं जानकारी लगने पर जिला शिक्षा अधिकारी और डीपीसी भी पहले छात्रा का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे और उसके बाद संबंधित स्कूल भी गए। अधिकारी ने स्कूल पहुंचकर संचालक को लताड़ भी लगाई। फिलहाल छात्रा का इलाज चल रहा है।

## महाकुंभ में भगदड़ से आस-पास के कई जिले प्रभावित कहीं स्कूल बंद तो कहीं रोके गए श्रद्धालु

**प्रयागराज-** महाकुंभ में हुए भगदड़ की वजह से प्रयागराज के आस पास के कई जिले प्रभावित हैं। किसी जिले में स्कूल बंद कर दिया गया है तो कई जिलों में गाड़ियों का जमावड़ा लग गया है। दरअसल, सोनभद्र से लेकर रायबरेली, फतेहपुर, चंदौली में ही श्रद्धालुओं को रोका गया है ताकि प्रयागराज में भीड़ को काबू में रखा जा सके। वहीं, रायबरेली में भारी भीड़ को देखते हुए स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया है। वहीं कई जगहों पर यात्रियों को होल्ड एरिया में रखा गया है। फतेहपुर की ओर से आने वाले यात्रियों को भी सीमा पर ही सुरक्षा बलो ने रोक लिया है। आपको बता दें कि सोनभद्र जिले में भी महाकुंभ व मौनी अमावस्या को लेकर प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं एक लम्बी कतार लगी हुई है। यहां से चार राज्यों के श्रद्धालु प्रयागराज की ओर एंट्री करते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने प्रयागराज में भीड़ के दबाव को कम करने के लिए सोनभद्र बार्डर पर हजारों श्रद्धालुओं रेलवे स्टेशन और बस डिपो पर ही रोक लिया है। सोनभद्र बॉर्डर से बिहार से आने वाले श्रद्धालुओं को सुअरसोत, झारखंड के श्रद्धालुओं को विंढमगंज, छत्तीसगढ़ से आने वाले श्रद्धालुओं को बभनी और मध्यप्रदेश से आने वालों को शक्तिनगर व घोरावल में रोका गया है। भीड़ को काबू करने के लिए डीएम, एसएसपी, एडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट समेत अन्य अधिकारी व फोर्स रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और सीमाओं पर तैनात की गई हैं। कई कुंभ स्पेशल ट्रेनों में यात्रियों को गंतव्य के लिए भेजा गया। लोगों को जान जोखिम में डालकर यात्रा नहीं करने की अपील की गई है।

# इंदौर-मनमाड़ रेल प्रोजेक्ट अब पीएमओ की सीधी निगरानी में

इंदौर। इंदौर-मनमाड़ रेल लाइन परियोजना अब पूरी तरह से प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की सीधी निगरानी में आ गई है, जिससे इसके कार्य में तेजी आने की उम्मीद है। इस परियोजना के तहत इंदौर जिले में भूमि अधिग्रहण के आदेश जारी हो चुके हैं। सांसद शंकर लालवानी ने बताया कि इस परियोजना के तहत कुल 13 जिलों की भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। महू के गांवों के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को गति देने हेतु अधिकारी की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिससे यह प्रक्रिया जल्द पूरी हो सके। इस परियोजना की कुल लंबाई 309 किलोमीटर होगी और यह इंदौर से मुंबई को जोड़ने के लिए बनाई जा रही है। सरकार ने सितंबर में इस प्रोजेक्ट के लिए 18,036 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी। इस नई रेल लाइन से यात्री सुविधाओं में सुधार होगा और औद्योगिक क्षेत्रों को मजबूत कनेक्टिविटी मिलेगी।

**59 गांवों की भूमि अधिग्रहण होगी** इस परियोजना का 170.56 किलोमीटर हिस्सा मध्य प्रदेश में आएगा, जिसमें 905 हेक्टेयर निजी भूमि शामिल है। इस परियोजना के तहत मध्य प्रदेश में 18 रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे, जिनमें महू, केलोद, कमदपुर, झाड़ी बरोदा और अन्य स्टेशन प्रमुख हैं। इसके अलावा, इंदौर और धुलिया जिले के कुल 59 गांवों की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इनमें इंदौर जिले के 22 गांव और धुलिया जिले के 37 गांव शामिल हैं। इंदौर-मनमाड़ रेलवे संघर्ष समिति के मनोज मराठे के अनुसार, रेल मंत्रालय द्वारा मध्य रेलवे के तहत इन गांवों की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

**18,036 करोड़ रुपए की मंजूरी** इंदौर-मनमाड़ रेल प्रोजेक्ट की योजना पर पिछले कई वर्षों से काम चल रहा है। 2022 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं मिल सकी थी, लेकिन 2023 में इसे 2 करोड़ रुपये की टोकन राशि जारी की गई। मध्यप्रदेश के हिस्से में डीपीआर और सर्वे का काम पूरा किया गया।

2024 के बजट में भी इस प्रोजेक्ट के लिए टोकन राशि दी गई थी, लेकिन अब इसे 18,036 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल गई है। यह राशि आगामी बजट में उपलब्ध कराई जाएगी।

**30 लाख लोगों को होगा फायदा** 309 किलोमीटर लंबी यह रेल लाइन इंदौर से महाराष्ट्र के मनमाड तक बिछाई जाएगी, जिससे करीब 30 लाख की आबादी को सीधा लाभ मिलेगा। रेलवे ने भूमि स्वामियों को उचित मुआवजा देने का आश्वासन दिया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने पर 16 जोड़ी यात्री ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, और शुरूआती वर्षों में अनुमानित 50 लाख यात्री इस सुविधा का लाभ उठाएंगे।

**समय और लागत बचेंगे** इंदौर-मनमाड़ रेल प्रोजेक्ट से इंदौर से मुंबई की दूरी 830 किलोमीटर से घटकर 568 किलोमीटर रह जाएगी, जिससे यात्रा में लगने वाला समय और लागत दोनों कम होंगे। यह रेल लाइन धार, खरगोन और बड़वानी जिले के आदिवासी अंचलों से गुजरेगी, जिससे इन क्षेत्रों को पहली बार रेलवे कनेक्टिविटी मिलेगी। इस परियोजना से न केवल यात्री सुविधाओं में सुधार होगा, बल्कि व्यापार और औद्योगिक क्षेत्रों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। इस परियोजना से रेलवे को हर साल लगभग 900 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होने की उम्मीद है।

**इंदौर में रेलवे पटरियों की हो रही सोनोग्राफी** रेल विभाग ने दिल्ली से मुबंई के रेलवे ट्रेक पर पटरियों की जांच शुरू की है। 70 हजार किलोमीटर लंबाई की पटरियों की ताकत के लिए उनकी सोनोग्राफी की जा रही है। पटरियों पर चलने वाली मशीन से हो रहे अल्ट्रासाउंड टेस्ट से ट्रेक पर जंग की स्थिति, उनकी वेल्डिंग की गुणवत्ता व उनके कमजर हिस्सों का पता लगाया जा रहा है। इस टेस्ट में एक अल्ट्रासोनिक मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। इंदौर के मुख्य रेलवे स्टेशन के एक नंबर और तीन नंबर प्लेटफार्म पर मशीन से पटरियां जांची की जा रही है। जब ट्रेक पर ट्रेन का आवागमन नहीं होता है, तब चार से पांच कर्मचारियों का दल यह काम करता है। ट्रेक की जांच कर रहे अफसरों ने बताया कि ट्रेन हादसे लोको पायलेट की गलती, ट्रेक में टूट-फूट या ट्रेन के भारी वस्तु से टकराने से होती है। देश में कई रुटों पर बरसों पुरानी पटरियां है। उन पर आए क्रेक से हादसे न हो, इसलिए पटरियों की जांच होती है। पटरियों की जांच के लिए इंट्रीग्रेटेड ट्रेक मॉनिटरिंग और ट्रेक रिकार्डिंग कार तकनीक का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन अल्ट्रा साउंड टेस्ट वाली यह स्वदेशी तकनीक ज्यादा आधुनिक है। आठ से दस लाख रुपये लागत की यह मशीन आसानी से एक दिन में 50 से 80 किलोमीटर ट्रेक की जांच आसानी से हो जाती है। मशीन को पटरियों पर रखकर चलाया जाता है। जिस हिस्से में भी ट्रेक की कमजोरी का पता चलता है। वहां से निकटवर्ती रेलवे स्टेशन की दूरी पताकर और निशान लगाकर जांच के लिए टीम आगे बढ़ जाती है।

# पैसों के विवाद में ऑटो रिक्शा चालक ने की इंस्पेक्टर की हत्या

इंदौर। इंदौर के खजराना इलाके में बीते शुक्रवार को मिले एक अज्ञात शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। मृतक की पहचान पुलिस रेडियो ट्रेनिंग स्कूल के इंस्पेक्टर प्रभात नारायण चतुर्वेदी के रूप में हुई, जिनकी हत्या एक ऑटो रिक्शा चालक ने पैसों के विवाद में कर दी थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी ड्राइवर देवेंद्र बोरासी निवासी नंदानगर गली नंबर 10 को गिरफ्तार कर लिया, जिसने पूछताछ में पत्थरों से इंस्पेक्टर की हत्या करने की बात कबूल की। दरअसल, इंस्पेक्टर चतुवेर्दी सोमवार तक घर नहीं पहुंचे, जिससे परिवार वालों ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट विजयनगर थाने में दर्ज कराई। इसके बाद जब पुलिस ने शुक्रवार को मिले अज्ञात शव की पहचान कराई तो यह चौंकाने वाला सच सामने आया। जांच में पता चला कि इंस्पेक्टर चतुवेर्दी की मां का हाल ही में पन्ना में निधन हो गया था, जिस कारण उनकी पत्नी पहले ही वहां जा चुकी थीं। इसी दौरान प्रभात नारायण घर से 50 हजार रुपए लेकर निकले थे। वे पहले स्कीम-74 स्थित अपने निमार्णाधीन मकान पर गए और फिर वहां से एक ऑटो में सवार होकर बेटे के होटल जाने की बात कही। लेकिन ऑटो

चालक ने उन्हें बायपास ले जाकर शराब पी और फिर रास्ते में पैसों को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान आरोपी देवेंद्र ने पत्थरों से हमला कर इंस्पेक्टर की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा करने के लिए 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। बायपास से लेकर रिंग रोड और विजयनगर तक कई फुटेज की जांच के बाद पुलिस को देवेंद्र के घर नंदानगर गली नंबर 10 की जानकारी मिली। जब पुलिस वहां पहुंची, तो उसे आरोपी का ऑटो खड़ा मिला, लेकिन वह खुद फरार था। इस आधार पर पुलिस को शक हुआ कि वही हत्यारा है। आगे की जांच में पुलिस को पता चला कि देवेंद्र हत्याकांड को अंजाम देने के बाद पंधाना भाग गया था। हालांकि, जब वह वापस इंदौर लौटा तो मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे धर दबोचा।

पूछताछ में देवेंद्र ने यह भी कबूल किया कि वह इंस्पेक्टर को पहले से नहीं जानता था। वह शराब पीने का आदी था और शादी न होने की वजह से डिप्रेशन में रहता था। हत्याकांड वाले दिन ज्यादा किराया देने को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ, जो इतना बढ़ गया कि देवेंद्र ने इंस्पेक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी। इस हत्याकांड ने पूरे इंदौर को हिला दिया, जबकि पुलिस की मुस्तैदी से आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया गया।

# इंदौर में आज से ग्लोबल स्पाइस समिट मसालों के अंतरराष्ट्रीय व्यापारी आएंगे

इंदौर। अपनी विशिष्ट संस्कृति और व्यंजनों एवं अनूठे स्वाद के लिए मशहूर के इंदौर में 30 और 31 जनवरी को दो दिन मसाले वालों का सम्मेलन होगा। देशभर के कोने कोने से आए मसाला व्यापारी एवं कारोबारी अपने इंदौर के होटल शेरेटन ग्रांड पैलेस में वैश्विक मसाला शिखर सम्मेलन का आयोजन कर रहे हैं। ग्लोबल स्पाइस समिट के 12वें संस्करण में देश विदेश में विख्यात मसाला उत्पादक कंपनियां भाग लेगी। इस अवसर पर मध्यप्रदेश शासन के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट सम्मेलन के दूसरे दिन मुख्य अतिथि रहेंगे। ग्लोबल स्पाइस समिट गत वर्ष राजस्थान की राजधानी पिंक सिटी जयपुर में आयोजित किया गया था। मसाला उद्योग की मांग पर इस बार इंदौर में आयोजन किया है। स्पाइस समिट में भारत से 300 से अधिक प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। समिट में उद्योग, थोक व्यापार, संबंधित सरकारी विभागों, प्रतिष्ठित अनुसंधान एवं विकास संस्थानों, व्यापार संघों और प्रौद्योगिकी पर आमंत्रित प्रतिष्ठित वक्ता विभिन्न विषयों पर अपने विचार और सुझाव रखेंगे।

**प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी** 30 एवं 31 जनवरी को

शेर्टन ग्रैंड पैलेस होटल में शिखर सम्मेलन के साथ-साथ मसालों, मसाला आधारित उत्पादों, सेवा प्रदाताओं और मशीनरी एवं उपकरण निमार्ताओं की एक प्रदर्शनी भी आयोजित की जा रही है। ग्लोबल स्पाइस समिट का आयोजन मसाला उद्योग और व्यापार से जुड़े निमार्ताओं, पैकर्स, प्रोसेसर, व्यापारियों, निर्यातकों, आयातकों, वैज्ञानिकों, सलाहकारों, संबंधित मशीनरी निमार्ताओं,सरकारी निकायों एवं अन्य संस्थाओं, शोध संस्थानों,बाजार और गुणवत्ता विशेषज्ञों, उद्यमियों आदि सभी हितधारकों को एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से किया जा रहा है, ताकि मसाला क्षेत्र के सतत विकास से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचारों को साझा करने के साथ ही सुझावों का आदान-प्रदान किया जा सके और व्यापारिक सौदे भी किए जा सकें।

**मसाला उद्योग की चुनौतियों पर होगी चर्चा** शिखर सम्मेलन मसाला उद्योग के सामने आने वाली चुनौतियों और अवसरों पर विचार-विमर्श करने का एक सुनहरा अवसर भी है। मसाला शिखर सम्मेलन-2025 में विभिन्न ताजा और प्रासंगिक विषयों पर पैनल चर्चा होगी। विशेष कर विभिन्न मसालों की खेती और उत्पादन अनुमान, जीरा, धनिया, लाल मिर्च, हल्दी सहित विभिन्न मसालों की मांग-आपूर्ति और मूल्य परिदृश्य, भारतीय मसालों के लिए वैश्विक बाजार, प्रसंस्करण एवं पैकेजिंग में तकनीकी नवाचार, मिलावट, गुणवत्ता एवं संदूषण संबंधी मुद्दे, उद्योग एवं व्यापार के समक्ष आने वाली चुनौतियां एवं उनके समाधान आदि विषयों पर विशेष चर्चा सत्र आयोजित होंगे।

**मसाला उद्योग के विकास में मदद मिलेगी** समिट की पृष्ठभूमि की जानकारी देते हुए राजेश गुप्ता ने बताया कि वैश्विक मसाला शिखर सम्मेलन मसाला निमार्ताओं और थोक आपूर्तिकताओं का एक प्रतिष्ठित सम्मेलन है। जिसका उद्देश्य मसाला उद्योग के नेताओं, नवोन्मेषकों और हितधारकों को एक मंच पर लाना है। शिखर सम्मेलन ज्ञान के आदान-प्रदान, नेटवर्किंग और सहयोग के लिए एक प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करता है। जो सभी प्रतिभागियों को मसाला क्षेत्र में नवीनतम विकास पर अपडेट रहने और मूल्यवान व्यावसायिक संबंध बनाने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। शिखर सम्मेलन न केवल व्यावसायिक प्रोफाइल को बढ़ाने में मदद करता है बल्कि पूरे मसाला उद्योग के विकास और जीवंतता में भी योगदान देता है।

# भाजपा से निष्कासित पार्षद जीतू यादव ने सोशल मीडिया पर बदली अपनी पहचान

इंदौर। छह साल के लिए भाजपा संगठन से बाहर किए गए पार्षद जीतू यादव की राजनीतिक भविष्य अब अंधेरे है। अब यादव ने बाबा साहेब आंबेडकर का सहारा ले लिया है। अपने फेसबुक अकाउंट से जीतू ने भाजपा का बैकग्राउंड हटाते हुए सॉची का स्तूप और बाबा साहेब आंबेडकर की फोटो लगाई है। इसके अलावा जीतू अपने सरनेम में यादव के साथ जाटव भी लिखने लगा है। जीतू ने पुलिस थाने पहुंचकर वाइस सैंपल तो दे दिए, लेकिन उस पर प्रकरण दर्ज होने का खतरा भी बना हुआ है,क्योकि यदि यह साबित हो जाता है कि समर्थकों को यादव ने कालरा के घर हमले के लिए भेजा था तो षड्यंत्र करने के मामले में उसे आरोपी बनाया जा सकता है।महापौर परिषद सदस्य बनाए

जाने पर नगर निगम में वाहन और प्रतिमाह 100 लीटर से ज्यादा डीजल सुविधा दी जाती है। इसके अलावा मोबाइल फोन, वायरलैस सेट और लैपटॉप भी जीतू को दिया गया था। वह भी जीतू ने लौटा दिया है। पार्षद कालरा कांड में पुलिस ने चालीस से ज्यादा आरोपी बनाए है। अब तक 21 आरोपी गिरफ्तार हो चुके है। 25 जनवरी को घटना के मुख्य आरोपी अवि यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद चार दिन से कोई नई गिरफ्तारी इस मामले में नहीं हो पाई है। इस मामले में अभी एक भी आरोपी की जमानत नहीं हुई है। सभी आरोपी जेल में बंद है। उधर यादव ने आवाज के जो नमूने पुलिस को दिए है। उसकी जांच पुलिस लैब में कराएगी। कालरा के साथ फोन पर हुए विवाद से उसका मिलान किया जाएगा।

# अखिल भारतीय महापौर केसरी कुश्ती प्रतियोगिता आज से

इंदौर। छोटा नेहरू स्टेडियम में गुरुवार से अखिल भारतीय महापौर केसरी कुश्ती प्रतियोगिता शुरू होने जा रही है। इसके पहले बुधवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव, महापौर केसरी कुश्ती अध्यक्ष व सामान्य प्रशासन प्रभारी नंदकिशोर पहाड़िया सहित निगम अधिकारी तैयारियां देखने पहुंचे। महापौर ने पार्किंग और ब्रांडिंग को लेकर जरूरी सुझाव दिए है। इस प्रतियोगिता में देशभर से पहलवान यहां आएंगे। अधिकारियों, प्रतियोगिताओं की व्यवस्था देखने वालों के साथ महापौर ने पार्किंग से लेकर जहां कुश्ती होगी वहां तक की सभी व्यवस्थाओं को देखा। साथ ही जहां कुछ बदलाव की जरूरत नजर आई, वहां भी बदलाव करने के लिए कहा। प्रतियोगिता की व्यवस्थाओं को देखने के बाद महापौर ने कहा कि हर बार नया आयाम, नया रंग लेकर महापौर केसरी पहले शहर में, फिर प्रदेश में और अब देश में इंदौर का संदेश देने को तैयार है। गुरुवार से महापौर केसरी प्रतियोगिता की शुरूआत होने जा रही है। उसके पहले हमने छोटा नेहरू स्टेडियम का दौरा किया। प्रतियोगिता में इस बार देशभर से पहलवान आने वाले है। विशेषकर महिला कुश्ती को लेकर बहुत आकर्षण है। लगभग 8 से 10 राज्यों से महिला पहलवान भी यहां आने वाले है। छोटा नेहरू स्टेडियम हर बार कि तरह इस बार भी सजकर तैयार है। ओपन होने से देशभर के कई अच्छे खिलाड़ी अपना परफॉर्मेंस देने यहां आएंगे। सभी के सहयोग से तीसरी बार महापौर केसरी बड़े स्तर पर कल से शुरू होने जा रहा है। पार्किंग और ब्रांडिंग को लेकर सुझाव दिए गए है। आशा है कि सभी खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे।

# महाराष्ट्र के गोंदिया के लिए फिर से शुरू होगी उड़ान

इंदौर। इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मार्च के आखिरी सप्ताह से लागू होने वाले समर शेड्यूल में दो महत्वपूर्ण सौगात मिली हैं। इस शेड्यूल में महाराष्ट्र के गोंदिया के लिए फिर से उड़ान शुरू की जाएगी, जबकि नोएडा के जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी इंदौर के लिए उड़ानें शुरू होंगी। डीजीसीए द्वारा जारी किए गए समर शेड्यूल में, इंदौर एयरपोर्ट को इन दोनों नए कनेक्शनों से बड़ी राहत मिलेगी। गोंदिया के लिए फिर से उड़ानें शुरू होने से इंदौर का सीधा कनेक्शन महाराष्ट्र के छह प्रमुख शहरों से हो जाएगा, जिसमें पहले से मुंबई, पुणे, नागपुर, शिरडी और नासिक के लिए फ्लाइट्स उपलब्ध हैं। गोंदिया के लिए पहले फ्लाय बिग एयरलाइन ने उड़ान शुरू की थी, जो बाद में बंद हो गई थी। अब फिर से इस रूट पर उड़ानें शुरू की जा रही हैं। इसी शेड्यूल में, इंदौर से बेंगलुरू के लिए एक नई फ्लाइट भी 16 फरवरी से शुरू होगी। यह फ्लाइट मंगलवार, गुरुवार और रविवार को सप्ताह में तीन दिन चलेगी। इंडिगो एयरलाइंस द्वारा संचालित होने वाली यह फ्लाइट इंदौर से सुबह 9:10 बजे रवाना होकर बेंगलुरू सुबह 11:15 बजे पहुंचेगी, और बेंगलुरू से दोपहर 12 बजे रवाना होकर इंदौर दोपहर 2:05 बजे पहुंचेगी। इस समर शेड्यूल के तहत, जेवर एयरपोर्ट से इंदौर के लिए उड़ान शुरू होने से दिल्ली एयरपोर्ट का दबाव भी कम होगा, क्योंकि यात्रियों के लिए नए विकल्प उपलब्ध होंगे।

# नगर निगम आयुक्त ने ली स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर बैठक

इंदौर। स्वच्छता सर्वेक्षण की गाइड लाइन के अनुसार सभी कामों को समय सीमा में करें। स्वच्छता अभियान में सफाई मित्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उनके लिए सभी वार्डों में बेहतर हाजिरी सेंटर बनाए जाए। यह बात बुधवार को नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने सिटी बस ऑफिस में स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 को देखते हुए ली एक बैठक में कही। उन्होंने निगम स्तर पर किए जा रहे कामों की जोनवार समीक्षा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि हाजिरी सेंटरों पर सफाई मित्रों और कर्मचारियों के लिए बैठने की

व्यवस्था होना चाहिए ताकि वे वहां आराम से बैठ सकें और खाना खा सके।

इसके साथ ही इंडोर गेम्स जैसे टेबल टेनिस, कैरम बोर्ड और अन्य मनोरंजक गतिविधियों की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए, जिससे सफाई मित्रों को आराम एवं मनोरंजन की सुविधा मिल सके। स्वच्छता सर्वेक्षण की तैयारियों को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए लगातार काम किया जा रहे हैं। नगर निगम आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे स्वच्छता सर्वेक्षण के सभी कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करें और इंदौर को एक बार फिर स्वच्छता में शीर्ष स्थान दिलाने हेतु पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। सभी अपनी फील्ड में रहे स्वच्छता सर्वेक्षण की टूलकिट का अच्छे से अध्ययन कर ले उसका पालन करें। बैठक में समस्त अपर आयुक्त, उपायुक्त, मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी, सीएसआई, उपयंत्री एवं अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।

# 20 साल बाद लोकायुक्त थाने की हवालात को सौरभ शर्मा ने किया 'आबाद'

भोपाल। मध्यप्रदेश लोकायुक्त थाने की हवालात में 20 साल बाद कोई आरोपी पहुंचा है। दरअसल, 2004 के बाद से लोकायुक्त ने गिरफ्तार कर हवालत में रखना बंद कर दिया था। अब 20 साल बाद आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा, चेतन सिंह गौर और शरद जायसवाल लोकायुक्त की सलाखों में पहुंचे हैं। बता दें कि 2004 में लोकायुक्त पुलिस ने कमर्शियल टैक्स विभाग के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर आरके जैन को गिरफ्तार किया था, उनको लोकायुक्त थाने की हवालात में रखा गया था। आरके जैन ने हवालात में आत्महत्या कर ली थी। आरके जैन की खुदकुशी के मामले में तत्कालीन लोकायुक्त डीएसपी समेत कई पुलिस कर्मचारियों को सस्पेंड कर दिया गया था और उनके खिलाफ जांच बैठा दी गई थी। उस समय मध्यप्रदेश में उमा भारती की सरकार थी। इस घटना से सरकार की किरकिरी हुई थी। इसके बाद लोकायुक्त ने गिरफ्तार कर हवालत में रखना बंद कर दिया था। अब 20 साल बाद सौरभ और उसके दो साथी लोकायुक्त की हवालत में पहुंचे हैं। सौरभ शर्मा और उसके दो साथियों को लॉकअप में रखने के रखने के सवाल पर लोकायुक्त एसपी दुर्गेश राठौर ने कहा कि हमने तीनों को कड़ी सुरक्षा के साथ रखा है।

**सौरभ शर्मा की डायरी के सफेदफोश होंगे बेनकाब** परिवहन विभाग में भ्रष्टाचार का सरगना आरटीओ का पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा 41 दिन बाद लोकायुक्त की गिरफ्त में आया है। मंगलवार को लोकायुक्त पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर कोर्ट के सामने पेश किया, जहां से उसे सात दिन की रिमांड पर भेज दिया गया। सौरभ के साथ ही लोकायुक्त की पकड़ में उसके साथी चेतन सिंह गौड़ और शरद जायसवाल भी आ गए। अब लोकायुक्त द्वारा तीनों से अलग-अलग और आमने-सामने बैठा कर पूछताछ की जा रही है। इसमें कांस्टेबल आरटीओ के बड़े घोटाले में कई बड़े खुलासे कर सकता है। शर्मा की गिरफ्तारी ने प्रदेश के कई बड़े नेता और अफसरों की सांसें फूला दी हैं। सौरभ शर्मा की परिवहन विभाग में नियुक्ति शिवराज सरकार में पूर्व मंत्री भूपेंर्द्र सिंह के कार्यकाल में हुई थी। उसकी नियुक्ति भी सवालों के घेरे में है। हालांकि, इन आरोपों पर भूपेंद्र सिंह जवाब दे चुके हैं कि कांस्टेबल की नियुक्ति में मंत्री का सीधा कोई दखल नहीं होता। 2016 से 2023 तक नौकरी में रहा सौरभ सौरभ शर्मा 2016 से 2023 तक नौकरी में रहा। इस बीच, कांग्रेस से भाजपा में आए गोविंद सिंह राजपूत, कमलनाथ और शिवराज सरकार में परिवहन मंत्री रहे। सौरभ शर्मा ने उनके कार्यकाल में करीब चार साल तक नौकरी की। दरअसल, कांग्रेस के कई बड़े नेता आरोप लगा चुके हैं कि एक कांस्टेबल इतना पैसा बिना किसी सफेदपोश और बड़े अधिकारी के संरक्षण के बगैर नहीं कमा सकता। इसमें गोविंद सिंह राजपूत पर भी आरोप लगे। हालांकि, राजपूत ने भी इन आरोपों पर जवाब दिया कि इस मामले में मेरा कोई लेना—देना नहीं है। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। जांच के बाद सब क्लियर हो जाएगा।

**डायरी में कई अधिकारियों के नाम** सौरभ के दोस्त चेतन गौर की गाड़ी में एजेंसी को एक डायरी मिली है, जिसमें प्रदेश के सभी जिलों के अधिकारियों के हिसाब किताब लिखा होने की बात सामने आई है। अब सौरभ और चेतन गौड़ पूछताछ में डायरी में किन अधिकारियों का लेखा जोखा है, उसका खुलासा कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि डायरी में उन अधिकारियों की पूरी डिटेल है, जिनको उगाही का हिस्सा देता था। ऐसे में कई अधिकारियों और नेताओं की अब धड़कनें बड़ी हुई हैं।

**जांच एजेंसी की कार्यप्रणाली पर खड़े हुए सवाल** सौरभ शर्मा के ठिकानों पर लोकायुक्त ने 19 दिसंबर को छापा मारा था। इसके बाद से वह फरार था। इसके बाद एजेंसियों के उसके दुबई जाने की बात कही। वहीं, रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया। हालांकि, बाद में उसके 23 दिसंबर को भारत लौट आने की जानकारी भी सामने आई। वह इसके बाद से दिल्ली समेत अलग-अलग शहरों में घूम रहा था। वह अपने परिवार के संपर्क में था। चौंकाने वाली बात यह है कि इस बीच वह भोपाल भी आया, लेकिन एजेंसियां सोती रहीं। सौरभ के वकील राकेश पाराशर ने दावा किया कि सोमवार को सौरभ कोर्ट आया और आवेदन पर हस्ताक्षर किए। इसके बावजूद एजेंसियों को कोई भनक नहीं लगी। ऐसे में अब जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में है।

**कार में मिला 52 किलो सोना दुबई, स्विटजरलैंड-ऑस्ट्रेलिया का** भोपाल के मेंडोरी के जंगल में इनोवा कार में मिले 52 किलो सोना और 11 करोड़ कैश के मामले की जांच डीआरआई (डायरेक्ट्रेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस) करेगा। अब तक की जांच में पता चला है कि सोने की मैन्युफैक्चरिंग दुबई, स्विटजरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की है। आरटीओ के करोड़पति पूर्व कॉन्स्टेबल सौरभ शर्मा, उसके दोस्त चेतन सिंह गौर और पार्टनर शरद जायसवाल की गिरफ्तारी के बाद आयकर विभाग और डीआरआई एक साथ पूछताछ कर सकते हैं। बताया जाता है कि 19-20 दिसंबर की रात इनोवा कार में जो सोना मिला था वह विदेश से मंगाया गया है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग दुबई, स्विटजरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की होने की बात सामने आई है। इसके बाद आयकर विभाग ने इसकी जानकारी डीआरआई को भी दे दी है। सोना और कैश की जांच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पार्ट है। सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों चेतन सिंह गौर, शरद जायसवाल व उनके रिश्तेदारों के ठिकानों पर लोकायुक्त, ईडी की छापेमारी में जब्त कैश और सोना के मामले में आयकर विभाग पूछताछ करेगा। आयकर इनके आय के स्त्रोत के आधार पर कार्रवाई करेगा। आयकर विभाग सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ के सभी विकल्पों पर विचार कर रहा है। विभाग यह देख रहा है कि क्या सौरभ की रिमांड की अवधि 4 फरवरी के पहले उससे बात हो सकती है? लोकायुक्त पुलिस की हिरासत में उससे पूछताछ संभव हो सकी तो लोकायुक्त पुलिस की मौजूदगी में उसके बयान लिए जा सकते हैं। आयकर विभाग के पास कोर्ट से भी टाइम लेकर पूछताछ करने का विकल्प है। अगर रिमांड अवधि के बाद सौरभ शर्मा को जमानत मिल जाती है तो फिर विभाग सीधे समन देकर बयान देने के लिए बुला सकता है।

**अरुण यादव ने भाजपा सरकार पर उठाए सवाल** पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस नेता अरुण यादव ने सौरभ शर्मा के मामले में भाजपा सरकार पर गंभीर सवाल उठाए हैं। यह तीसरी बार है जब उन्होंने सरकार से सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि सौरभ शर्मा के राज से किस-किस पर गिरेगी गाज? यादव ने इस मामले में कई सवाल उठाते हुए कहा कि जब सौरभ शर्मा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था, तो फिर जांच एजेंसियों को उसके देश और प्रदेश में आने की जानकारी क्यों नहीं मिली? उन्होंने आगे सवाल किया कि क्या एजेंसियां सही तरीके से जांच कर रही हैं, या फिर सभी जांच एजेंसियां सौरभ शर्मा को बचाने में लगी हुई हैं? यादव ने यह भी पूछा कि सौरभ शर्मा 24 घंटे तक भोपाल में कहां रुका था और इस दौरान जांच एजेंसियां पूरी रात क्यों सोई रहीं? अरुण यादव ने यह भी आरोप लगाया कि इन 24 घंटों के दौरान सौरभ शर्मा को संरक्षण दिलाने की सारी व्यवस्थाएं क्या किसी मौजूदा मंत्रिमंडल के सदस्य ने की थीं? उन्होंने यह सवाल भी किया कि क्या सौरभ शर्मा से होने वाली पूछताछ की वीडियो रिकॉर्डिंग सार्वजनिक की जाएगी?

# भोपाल में 20 हजार से ज्यादा खानपान की दुकानों के लाइसेंस नहीं

## खाने के सामान में भी भारी मात्रा में मिलावट



**भोपाल।** आजकल हर व्यक्ति बाहर का खाना बहुत पसंद करता है। इसके चलते शहरों में खानपान की दुकानें और फूड स्टॉल की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। भोपाल शहर की बात करें तो बीते एक साल में करीब साढ़े तीन हजार खानपान की दुकानें खुल गई। साल 2020 के बाद इनकी संख्या में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है। हालांकि इसके अनुपात में फूड लाइसेंस भी बने। इस समय करीब 2800 फूड लाइसेंस जारी किए गए हैं। इसके बाद भी यहां हजारों की संख्या में ऐसे खानपान के दुकान वाले है जिन्होंने फूड लाइसेंस नहीं लिए हुए हैं। इनमें खाना बनाकर खिलाने से लेकर फूड आइटम बेचने की दुकानें शामिल है। खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने फुटपाथ वाले दुकानदारों को निशुल्क लाइसेंस की सुविधा दी गई है। शहर में बढ़ती आबादी और लोगों के बाहर खाना खाने का कल्चर बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए फूड कारोबार से जुडे एक रेस्टॉरेंट मालिक विपिन श्रीवास्तव का कहना है कि शहर में करीब छोटे-बड़े मिलाकर 15 हजार से अधिक खाने पीने की दुकानें, स्टॉल और होटल हैं। इतना ही नहीं फुटपाथ में लगने वाली दुकानों से भी करीब 4-5 हजार रुपए तक का खाने का सामान बिकता है। वहीं, होटल और रेस्टॉरेंट में इनकी संख्या ज्यादा है। इस तरह करीब 20 करोड़ का खाना-पीना बाहर होता है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि फूड एक्ट के तहत लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस होती है। हॉकर्स और फुटपाथ वाले दुकानदारों के लिए फ्री में रजिस्ट्रेशन की सुविधा दी गई है। एमपी ऑनलाइन के माध्यम से या फिर खुद ही डिपार्टमेंट की साइड से जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अधिकारी ने बताया कि फूड स्टॉल में उनकी जांच का शेड्यूल फिक्स रहता है। इसके अलावा शिकायत पर भी जांच करते हैं। फूड सेफ्टी ऑफिसर ने लोगों को सलाह देते हुए कहा कि उनको भी जागरुक रहना चाहिए। वे जिस भी दुकान में जाएं वहां फूड लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन की स्थिति जरूर देखें। आप जिस भी दुकान पर खाने-पीने का सामान खरीदने जा रहे हैं। वहां पर रजिस्ट्रेशन और फूड लाइसेंस देखें। खाने पीने की दुकान पर यदि रजिस्ट्रेशन और फूड लाइसेंस नहीं लगाया गया है तो उसके बारे में दुकानदार से पूछे। इसके चलते उपभोक्ताओं को शुद्ध सामग्री मिल सके। फूड एंड सेफ्टी स्टेंडर्ड एक्ट 2006 के तहत बिना लाइसेंस लिए खाद्य सामग्री बेचने पर भारी जुमार्ने का प्रावधान है।

# जय श्री गायत्री फूड कंपनी पर भोपाल, मुरैना और सीहोर में ईडी का छापा

भोपाल। मध्यप्रदेश में जय श्री गायत्री फूड के मुख्यालय पर प्रवर्तन निदेशालय (एऊ) की टीम ने छापा मारा। गायत्री फूड कंपनी डेयरी प्रोडक्ट्स तैयार करती है। बुधवार सुबह ईडी की टीम ने प्रदेश की राजधानी भोपाल, मुरैना, सीहोर समेत कंपनी के अन्य ठिकानों पर एक साथ छापा मारा। बताया जा रहा है कि कंपनी के प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं, जिन्हें भेजने के लिए फर्जी सर्टिफिकेट तैयार किए जा रहे थे। फर्जी सर्टिफिकेट से कारोबार कर विदेशी निवेश किया जा रहा है। जिसकी शिकायत के बाद ईडी ने कार्रवाई की। इससे करीब छह महीने पहले इस कंपनी पर ईओडब्ल्यू (इकोनॉमिक ऑफेंस विंग) ने भी छापेमारी की थी। कार्रवाई के दौरान जानकारी सामने आई है कि 27 देशों में भेजे जाने वाले प्रोडक्ट्स के सर्टिफिकेट फर्जी हैं। साथ ही दूसरे देशों की कई एजेंसियों ने अमानक खाद्य पदार्थों को लेकर केंद्र सरकार से शिकायत की थी। इसके आधार पर टीम ने कंपनी के ठिकानों पर छापा मारा। ईडी की टीम राजधानी भोपाल के बिट्टन मार्केट के पास स्थित कंपनी के ऑफिस में कार्रवाई कर रही है। वही, सीहोर रातीबड़ भोपाल मार्ग पर ग्राम पिपलिया मीरा में स्थित जय श्री गायत्री पनीर फैक्ट्री पर भी छापामार कार्रवाई जारी है। सुबह पुलिस के जवानों के साथ अधिकारियों का दल ग्राम पिपरिया मीरा में स्थित जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट पनीर फैक्ट्री पहुंचा और जांच पड़ताल शुरू की। इसके अलावा ईडी की एक टीम फैक्ट्री प्रबंधन के मुरैना स्थित ठिकाने पर भी पहुंची है।

# भोपाल का चौथा रेलवे स्टेशन निशातपुरा जल्द शुरू होगा, तैयारियां पूरी

भोपाल। राजधानी भोपाल का चौथा रेलवे स्टेशन जल्द ही शुरू हो जाएगा। इसके लिए तैयारियां पूरी की जा चुकी है। यह स्टेशन भोपाल से आगे निशातपुरा है। यहां पर करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं के माध्यम से उन्नत किया गया है। स्टेशन पर नवनिर्मित प्लेटफॉर्म, पैदल पार पुल, यात्री लिफ्ट, रैंप और प्रतीक्षालय सहित अन्य सुविधाओं का विस्तारीकरण किया गया है। मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ वेरावल एक्सप्रेस को निशातपुरा स्टेशन से ही संचालित किया जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह ट्रेनें भोपाल नहीं आएंगी। भोपाल के निशातपुरा रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को सांसद आलोक शर्मा ने निरीक्षण किया। उन्होंने भोपाल और रानी कमलापति स्टेशन पर यात्री भीड़ कम करने के लिए इस स्टेशन को शुरू करने का निर्देश भी दिया। सांसद शर्मा ने रेलवे अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए, जिनमें सेंट्रल वेयरहाउस का गोदाम हटाकर यात्रियों के लिए सुगम एंट्री गेट बनाना प्रमुख है। उन्होंने मालवा एक्सप्रेस और सोमनाथ वेरावल एक्सप्रेस को निशातपुरा स्टेशन से संचालित करने का निर्देश दिया, जिससे भोपाल और रानी कमलापति स्टेशन पर यात्री भीड़ कम होगी। सांसद आलोक शर्मा ने बताया कि वे जल्द ही रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात कर स्टेशन के शुभारंभ की तारीख तय करेंगे। उम्मीद जताई गई है कि फरवरी के अंत तक स्टेशन यात्रियों के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। वहीं, रेलवे के अधिकारियों के अनुसार भोपाल मंडल की ओर से स्टेशन के शुरू करने के संबंध में पूरी तैयारी है। पहले चरण में यहां 14 ट्रेनों को ठहराव दिया जा सकता है।

## हाईकोर्ट के फैसले के बाद कमलनाथ ने की बड़ी मांग

# सभी भर्तियों में 27 प्रतिशत ओबीसी रिजर्वेशन लागू करें



भोपाल। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को लेकर याचिका खारिज कर दी है। याचिका खारिज किए जाने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य सरकार से ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिए जाने की मांग की है। मध्यप्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बुधवार को कहा कि हाईकोर्ट ने उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें राज्य शासन द्वारा प्रदेश में 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण देने के फैसले का विरोध किया गया था। यह कांग्रेस पार्टी की नीतियों की जीत है। उन्होंने कहा कि मार्च 2019 में जब वे मुख्यमंत्री थे तो मध्यप्रदेश के ओबीसी समुदाय को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान किया था। हाईकोर्ट के फैसले ने तत्कालीन सरकार के निर्णय को एक बार फिर सही साबित किया है। अब मध्यप्रदेश सरकार को तत्काल सभी स्तर पर 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण देना सुनिश्चित करना चाहिए। कांग्रेस नेता ने भाजपा पर ओबीसी विरोधी होने का आरोप लगाते हुए कमलनाथ ने कहा कि ओबीसी आरक्षण को लेकर भाजपा ने हमेशा षड्यंत्रकारी रवैया अपनाया है। अगर पिछले छह साल के घटनाक्रम को देखें तो यह बात और ज्यादा स्पष्ट हो जाती है। कमलनाथ ने आगे कहा कि जब भाजपा सरकार आई, तो उन्होंने 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण के हमारे फैसले को कमजोर करने का काम किया। भाजपा सरकार ने 14% आरक्षण के साथ भर्तियां करने का फैसला लिया और 13% आरक्षण को होल्ड कर दिया। इससे ओबीसी वर्ग को सीधे तौर पर नुकसान हुआ। कमलनाथ ने कहा कि 28 जनवरी 2025 को हाई कोर्ट का फैसला ओबीसी आरक्षण के पक्ष में आने के बाद अब राज्य सरकार को जल्द से जल्द 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह ओबीसी वर्ग का अधिकार है, जिसे कांग्रेस ने सुनिश्चित किया था और अब यह भाजपा सरकार की जिम्मेदारी है कि वे इसे लागू करें।

**हमारी सरकार ने किया ओबीसी आरक्षण देने का फैसला** कमलनाथ ने कहा कि मार्च 2019 में मेरी तत्कालीन सरकार ने मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया था। उसी साल 19 मार्च को हाईकोर्ट ने पोस्टग्रेजुएट मेडिकल कोर्स के लिए 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण पर स्थगन दिया। गौरतलब है कि स्थगन सिर्फ कुछ नौकरियों के लिए था। इतना ही नहीं ओबीसी के 27 प्रतिशत रिजर्वेशन की सभी बाधाओं को दूर करने के लिए जुलाई 2019 में मेरी सरकार ने विधानसभा से 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण का कानून भी पास कर दिया था।

**ओबीसी के खिलाफ षड्यंत्र हुआ** पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मार्च 2020 में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनने के बाद ओबीसी के खिलाफ षड्यंत्र शुरू किया गया। हाई कोर्ट का आदेश सिर्फ कुछ पदों पर लागू होना था लेकिन भाजपा सरकार ने पूरे राज्य में सभी जगह यह आदेश लागू कर 27 प्रतिशत आरक्षण की हत्या कर दी।

**राज्य सरकार का 87:13 फार्मूला खारिज** मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार के 87:13 फार्मूले को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दीं। इस फार्मूले का इस्तेमाल सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों के लिए किया जाना था। यह मामला ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने से जुड़ा है। हाईकोर्ट ने 27% ओबीसी आरक्षण पर रोक बरकरार रखी है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर खंडपीठ ने एक अहम फैसले में राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 87:13 के फार्मूले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। यह फार्मूला सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण से जुड़े विवाद के बीच नियुक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए सुझाया गया था। इस फैसले के साथ ही कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% करने पर लगी रोक को भी बरकरार रखा है। यह मामला पूर्ववर्ती कमलनाथ सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश से शुरू हुआ था, जिसे बाद में कानून बना दिया गया था। इस कानून के तहत ओबीसी आरक्षण को 14% से बढ़ाकर 27% कर दिया गया था। इसके बाद कई याचिकाएं हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में दायर की गईं। कुछ याचिकाएं इस कानून के समर्थन में थीं तो कुछ विरोध में। हाईकोर्ट ने इस कानून पर रोक लगा दी थी। इसी बीच, राज्य सरकार ने नियुक्तियों को आगे बढ़ाने के लिए 87:13 का फार्मूला सुझाया। इस फॉम्युर्ले के तहत, विज्ञापित पदों में से 87% पर नियुक्तियां की जानी थीं। बाकी 13% पदों के लिए सामान्य और ओबीसी उम्मीदवारों की दो अलग-अलग सूचियां बनाई जानी थीं। इन सूचियों में मेरिट के आधार पर सबसे कम अंक वाले उम्मीदवारों को शामिल किया जाना था। इन उम्मीदवारों के परिणाम रोक दिए जाते और कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद ही नियुक्तियां दी जातीं।

# स्टेट म्यूजियम में गूंजा लोक गायन...गीत संगीत से सजी शाम

भोपाल। राजधानी भोपाल में श्यामला हिल्स सुरम्य पहाड़ियों पर बसे राज्य संग्रहालय की दहलीज पर एक संगीत भरी शाम की सौगात आई। गत एक सप्ताह से जारी युगकालीन सिक्कों की प्रदर्शनी के समापन अवसर को इस खास रंगत के साथ सजाया गया था। भक्ति गीतों से हुई शुरूआत के बीच गणतंत्र पर्व को समर्पित देशभक्ति गीत भी यहां लहराए। बाद में लोक गीत और लोक नृत्य से भी मौजूद श्रोता और दर्शक झूमते नजर आए। इस संगीतभरी खास प्रस्तुति के लिए उत्तर प्रदेश से प्रसिद्ध लोक गायक सुरेश कुशवाह और उनकी टीम भोपाल पहुंची थी। पुरातत्व संचालनालय व अभिलेखागार एवं संग्रहालय भोपाल ने डॉ विष्णु श्रीधर वाकणकर पुरातत्व एवं शोध संस्थान के साथ यह आयोजन किया था। जिसके अंतर्गत अश्विनी शोध संस्थान महिदपुर(उज्जैन) ने युग युगीन सिक्कों की प्रदर्शनी और इसी पर आधारित व्याख्यान माला का आयोजन किया था। एक सप्ताह के इस आयोजन का मकसद नई पीढ़ी को अपने देश और प्रदेश की विरासत से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों से वाकिफ कराना था। कार्यक्रम के समापन सत्र में आयोजित सांस्कृतिक संध्या का आगाज संस्कृति विभाग के प्रमुख सचिव शिवशेखर शुक्ला ने किया। कार्यक्रम में संस्कृति सचिव और पुरातत्व विभाग की आयुक्त श्रीमती उर्मिला शुक्ला, निदेशक डॉ पूजा शुक्ला भी अतिथियों में शामिल थीं।

**व्याख्यान माला में रेखांकित हुए सिक्के** कार्यक्रम के प्रारंभ में आयुक्त उर्मिला शुक्ला ने द्वारा युग-युगीन सिक्कों की प्रदर्शनी और इस पर आधारित व्याख्यान माला के उद्देश्य पर प्रकाश डाला। ये सिक्के अश्विनी शोध संस्थान महिदपुर के संग्रह से लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सिक्के समसामयिक, ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक अध्ययन के महत्वपूर्ण स्त्रोत के रूप में जीवंत प्रमाण हैं। यहां प्रदर्शित सिक्के भारत की प्राचीनतम निष्क के रूप में प्रचलित प्राचीनतम सिक्कों से लेकर आहत मुद्राएं, बेंट बार सिक्के, कुषाण, शक क्षत्रप, गुप्तकालीन, स्वर्ण मुद्राएं, मध्यकालीन, चौहान, चाणक्य, परमार कालीन सिक्के, मुगल शासक जहाँगीर के सिक्के एवं देशी रिसायत के सिक्के प्रदर्शित हैं। जिनमें गुप्त शासक राम गुप्त के सिक्के एवं पर्यावरण के संदेश देते बाग के मध्य नहर युक्त एवं मत्स्य, कच्छप आदि अंकित सिक्के, शिव के महाकाल स्वरूप के अंकन युक्त सिक्के शामिल हैं।

**छाया संगीत का जादू** सुरेश कुशवाहा हिन्दी गीत, गजल, भजन गायन के क्षेत्र में लब्ध प्रतिष्ठित गायक हैं। कुशवाहा एवं उनके दल द्वारा कार्यक्रम के आरम्भ में साहिल कुमार द्वारा श्रीराम पर आधारित भजन का गायन किया गया। इसके बाद मध्यप्रदेश की संस्कृति पर आधारित भजन का गायन किया गया। कलाकारों ने भारतीय संस्कृति पर आधारित लोक गीत गाए गए। लोक नृत्य की प्रस्तुति की श्रृंखला में लोक गायिका जया ने एक से एक गीत प्रस्तुत किए और उपस्थित श्रोताओं और दर्शकों की वाह-वाही लूटी।

संपादकीय

# समान नागरिक संहिता को लागू करना अवैध और असंवैधानिक नहीं

**समान नागरिक संहिता कोई 'संघी व्यवस्था' नहीं है। संविधान बनाने वाले हमारे पुरखों ने अनुच्छेद 44 में यह प्रावधान निहित किया था कि केंद्र अथवा राज्य सरकारें समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रयास जरूर करें। देश की सर्वोच्च अदालत ने भी इसकी पक्षधरता कुछ अवसरों पर व्यक्त की है। तो यह बुनियादी निष्कर्ष तय है कि समान संहिता को लागू करना अवैध और असंवैधानिक नहीं है। उत्तराखंड में यह भाजपा सरकार ने ही तय नहीं किया है, बल्कि सर्वोच्च अदालत की न्यायाधीश रह चुकीं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 2.35 लाख लोगों से विमर्श किया गया।**

भाजपा ही नहीं, भारतीय जनसंघ का भी एक बुनियादी, वैचारिक एजेंडा देश के एक राज्य में लागू हो गया है। समान नागरिक संहिता को कानूनन उत्तराखंड राज्य ने लागू किया है। अभी भाजपा शासित 6-7 राज्य और हैं, जहां समान नागरिक संहिता की दिशा में लगातार प्रयास जारी हैं। वहां से भी जल्द ही अच्छी खबरें आ सकती हैं। केंद्र के स्तर पर कब होगा, फिलहाल यह निश्चित नहीं है। उत्तराखंड देश का सर्वप्रथम राज्य बन गया है। भाजपा के मातृ-दल जनसंघ ने अनुच्छेद 370 को समाप्त करने और तीन तलाक को कानूनन बनाने सरीखे मुद्दों को अपना वैचारिक एजेंडा तय किया था और उसी के आधार पर राजनीति की थी। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण भाजपा और विहिप का साझा एजेंडा था। आरएसएस बांग्लादेशी घुसपैठियों को देश के बाहर खदेड़ने का पक्षधर रहा है। देखा जाए तो ये संघ परिवार के ही वैचारिक मुद्दे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन मुद्दों को साकार कराया है, बेशक समान नागरिक संहिता पर वे राज्यवार चलना चाहते हैं। यह बचाव-मुद्रा इसलिए है, ताकि देशभर में सांप्रदायिक बवाल न मचे और दंगों की नौबत न आए। उत्तराखंड ने जो पहल की है, उसका भी त्वरित विरोध 'जमायत-ए-हिंद' ने किया है और समान संहिता को मुसलमानों के मजहबी हुकूक में दखलअंदाजी माना है। उन्होंने इस कानूनी व्यवस्था को सर्वोच्च अदालत में चुनौती देने का भी ऐलान किया है। वैसे समान नागरिक संहिता कोई 'संघी व्यवस्था' नहीं है। संविधान बनाने वाले हमारे पुरखों ने अनुच्छेद 44 में यह प्रावधान निहित किया था कि केंद्र अथवा राज्य सरकारें समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रयास जरूर करें। देश की सर्वोच्च अदालत ने भी इसकी पक्षधरता कुछ अवसरों पर व्यक्त की है। तो यह बुनियादी निष्कर्ष तय है कि समान संहिता को लागू करना अवैध और असंवैधानिक नहीं है। यह भाजपा सरकार ने ही तय नहीं किया है, बल्कि सर्वोच्च अदालत की न्यायाधीश रह चुकीं जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में 2.35 लाख लोगों से विमर्श किया गया। उस प्रक्रिया के बाद ही 740 पन्नों का मसविदा सामने आया। उसे विधानसभा में पारित किया गया, फिर राज्यपाल ने सहमति दी और 12 मार्च, 2024 को राष्ट्रपति ने अनुमोदित किया। विमर्श की गुंजाइश अब भी है। साफ है कि समान नागरिक संहिता के तहत सभी धर्मों के सभी लोगों को समान अधिकार देने की व्यवस्था की गई है। सवाल यह है कि अनुसूचित जनजातियों को भी इससे अलग क्यों रखा गया है? आदिवासी अब पूरी तरह कबीलाई नहीं हैं। वे भी सुशिक्षित हैं, सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, आईएएस/आईपीएस अधिकारी भी हैं। नए दौर, नए युग की करवटें वे भी देख रहे हैं। उन आदिवासियों को इस कानून से अलग रखा जा सकता था, जो आज भी अनपढ़ हैं और जंगल की जिंदगी जी रहे हैं। बहरहाल समान नागरिक संहिता में विवाह, तलाक, बहुविवाह, बाल विवाह, बेटा-बेटी बराबर, गोद लेने की कानूनी व्यवस्था, विरासत, वसीयत और लिव-इन सरीखी तमाम व्यवस्थाएं समान रूप से लागू की जा सकती हैं। उत्तराखंड ने अपने कानून में 'हलाला' को 'अपराध' करार दिया है। धारा 63 और 51, महिला से क्रूरता या उत्पीड़न धारा 69 में अपराध है। हलाला पर 10 साल तक जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। शादी, तलाक, उत्तराधिकार और विरासत के नियम सभी धर्मों और समुदायों के लिए समान होंगे। इससे हलाला जैसी कुप्रथाओं का अंत होगा और महिलाओं को समान अधिकार सुनिश्चित किए जाएंगे। बिना पंजीकरण के लिव-इन संबंध एक महीने से अधिक चलने पर तीन महीने की कैद या 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। विवाह पंजीकरण न होने पर 25,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। विवाह और लिव-इन संबंधों का पंजीकरण ऑनलाइन करने के लिए एक डिजिटल पोर्टल उपलब्ध कराया गया है। बच्चों के जन्म प्रमाणपत्र सात दिनों के भीतर पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यूसीसी के तहत एक पत्नीत्व को सुनिश्चित किया गया है। विवाह के समय किसी व्यक्ति का अन्य जीवनसाथी जीवित नहीं हो सकता है। वसीयतनामे में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आधार आधारित दस्तावेजीकरण और गवाहों की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य किया गया है। लड़कियों और लड़कों को उत्तराधिकार में समान अधिकार मिल गया है। उत्तराखंड सरकार के इस निर्णय को महिलाओं को समान अधिकार दिए जाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। हलाला जैसी प्रथाओं को समाप्त करने और लड़कियों को समान विरासत अधिकार देने के प्रावधानों को महिला सशक्तिकरण और समानता की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। यूसीसी लागू करने के लिए अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है और अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नियमों को मंजूरी दी गई है। यह कदम राज्य को समता और न्याय की ओर अग्रसर करेगा। बहरहाल समान नागरिक संहिता देशभर में लागू क्यों न की जाए?

# गांवों की खुशहाली मापने के लिए बनाएं नए मानदंड

**ग्रामीण इलाके में जैसी समृद्धि दिखनी चाहिए, कम से कम जमीनी स्तर पर वैसी समृद्धि नहीं है। गांवों का जैसा रूप होना चाहिए, वैसा नहीं है। इसलिए सिर्फ घरेलू खर्च के जरिये ही गांवों की खुशहाली और समृद्धि की खोज करना उचित नहीं होगा। यह तभी होगा, जब गांवों की खुशहाली और समृद्धि मापने के लिए समन्वित और समावेशी मूल्यांकन प्रणाली अपनाएंगे, जिसमें यह भी देखा जाएगा कि कितनी ग्रामीण आबादी को मजबूरी में गांव पीछे छोड़ना पड़ा है और कितनी आबादी गांव लौट रही है।**

दुनिया की पांचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था वाले अपने देश की पहचान उसके गांव रहे हैं। देश सिर्फ ग्रामीण संस्कृति और कृषि व्यवस्था के लिए ही नहीं, सहकार और शिल्पकारी के लिए भी वैश्विक पहचान रखते रहे हैं। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले दौर में भी भारतीय कृषि और आर्थिकी के आधार गांव ही रहे। यह बात और है कि अंग्रेजी शासन के दौरान से भारतीय गांवों का पतन शुरू हुआ। इसके बाद भारतीय गांव गरीबी और मजबूरी के पर्याय माने जाने लगे। लेकिन घरेलू उपयोग और खर्च के ताजा सर्वेक्षण की रिपोर्ट बता रही है कि गांवों की आर्थिक तस्वीर बदलने लगी है। भारत सरकार के सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की ओर से घरेलू उपयोग और खर्च के लिए कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार शहरी और ग्रामीण इलाकों में घरेलू खर्च का जो पहले अंतर रहता था, वह लगातार घटता चला गया है। अगस्त 2023 से जुलाई 2024 के दौरान किए गए सर्वेक्षण के मुताबिक, ग्रामीण और शहरी भारत में प्रति व्यक्ति औसत मासिक खर्च 4,122 रुपए और 6,996 रुपए हो गया है। जबकि पहले यानी 2022 से 2023 के बीच यह खर्च क्रमशः 3,773 रुपए और 6,459 रुपए था। यानी शहरी और ग्रामीण भारत की प्रति व्यक्ति खर्च दर में बड़ा अंतर था। मोटे तौर पर यह आंकड़ा बता रहा है कि हाल के दिनों में ग्रामीण इलाकों में आर्थिक समृद्धि पहले की तुलना में बढ़ी और उस लिहाज से खर्च भी बढ़ा है।

2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 68 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, जबकि 32 प्रतिशत आबादी शहरों में है। स्वाधीन भारत में विशेषकर उदारीकरण के बाद जिस तरह का विकास मॉडल हमने अपनाया, उसमें शहरी विकास पर सबसे ज्यादा फोकस रहा, ग्रामीण विकास या तो रस्मी रहा या फिर उस पर फोकस शहरों की तुलना में कम रहा। शहरों की ओर रोजगार और जीवन सुविधाएं केंद्रित होती चली गईं। शिक्षा के भी बेहतर अवसर गांवों की तुलना में शहरों की ओर बढ़ते गए। इस लिहाज से ग्रामीण क्षेत्रों से सबसे ज्यादा पलायन रोजगार और शिक्षा के लिए हुआ। फिर जिन परिवारों के पास सहूलियतें बढ़ीं, उन परिवारों ने अपनी हैसियत और बजट के लिहाज से मुफीद पाए जाने वाले शहरों की ओर रहने के लिए रूख किया। यही वजह है कि शहरी और ग्रामीण आबादी का जो अनुपात आबादी के समय था, वह आज बदल चुका है। आजादी के वक्त तकरीबन 80 फीसदी से ज्यादा लोग गांवों में रहते थे, अनुमान है कि वह घटते-घटते अब साठ और पैंसठ फीसदी के बीच आ गई है। रिकॉर्ड पर ग्रामीण आबादी का इतना बड़ा हिस्सा भले ही गांवों में बसता हो, लेकिन हकीकत यह है कि इसमें एक बड़ा हिस्सा शहरों में रोजी-रोटी और शिक्षा के लिए कभी शौकिया तो कभी मजबूरीवश रहने को मजबूर है। इसलिए रिकॉर्ड की तुलना में वास्तविक ग्रामीण आबादी अब और भी कम हो चुकी है।

घरेलू खर्च के इस नए आंकड़े को देखते वक्त हमें इस संदर्भ पर भी ध्यान देना होगा। बहरहाल हमें यह भी ध्यान देना होगा कि ग्रामीण इलाकों में खाद्यान्न विशेषकर गेहूं और चावल पर खर्च में निजी या पारिवारिक खर्च में कमी आई है। इसकी वजह यह है कि सरकार की ओर से तमाम तरह की योजनाएं और सामाजिक कल्याण कार्यक्रम चल रहे हैं। मुफ्त खाद्यान्न योजना समेत कई अन्य सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के जरिये मुफ्त में मिल रही चीजों की कीमतों को ध्यान में रखें तो घरेलू खर्च के ये आंकड़े ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए क्रमशः 4,247 रुपए और 7,078 रुपए हो जाते हैं। मौजूदा कीमतों के संदर्भ में देखें तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति खर्च पर औसत आठ और नौ प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। साल 2011-12 में शहरी और खपत खर्च के बीच 84 प्रतिशत का अंतर था, जो 2022-23 में घटकर 71 प्रतिशत हो गया। जो अब 70 फीसद ही रह गया है। इन आंकड़ों से ग्रामीण इलाकों में बढ़ती खुशहाली की तसवीर सामने आती है। दिलचस्प यह है कि इस आंकड़े में खाने-पीने के अलावा की चीजों पर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में यह खर्च 60 और 53 प्रतिशत रहा। इसका मतलब साफ है कि अब ग्रामीण इलाकों में भी वाहन, कपड़े, बिस्तर, जूते, मनोरंजन एवं टिकाऊ आदि सामानों पर खर्च बढ़ा है। इससे साफ है कि उपभोक्तावाद ने ग्रामीण इलाकों पर भी जोरदार दस्तक दी है। वैसे ऑनलाइन स्टोर से गांवों में खरीददारी बढ़ी है और उनके डिलीवरी एजेंटों की बाइकें अब ग्रामीण इलाकों का भी खूब चक्कर लगा रही हैं।

पिछले साल मई में रिजर्व बैंक ने भी ग्रामीण इलाकों में बढ़ती खपत खर्च को लेकर ऐसे ही आंकड़े जारी किए थे। इन्हीं आंकड़ों के आधार पर रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने उम्मीद जताई थी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी रहेगी और देश की जीडीपी दर मे 7.3 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हो सकती है। लेकिन रिजर्व बैंक ने इसी रिपोर्ट में ग्रामीण इलाकों में बढ़ते कर्ज को लेकर भी रिपोर्ट जारी की थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की रिपोर्ट में भी कर्ज को लेकर चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। इसके मुताबिक, कर्ज लेने में ग्रामीण क्षेत्रों के लोग कहीं ज्यादा आगे हैं। गांवों में प्रति एक लाख लोगों में 18,714 लोग ऐसे हैं, जिन्होंने कोई न कोई कर्ज ले रखा है, जबकि शहरों में यह आंकड़ा 17,442 प्रति लाख ही है। साफ है कि उपभोक्तावाद ग्रामीण संस्कृति को बदलने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। कर्ज कभी गांवों के लोगों के लिए सिरदर्द होते थे, इसलिए वहां बचत केंद्रित आर्थिकी पर जोर था। लेकिन अब इसमें गिरावट आई है। इसका मतलब साफ है कि गांवों में खर्च भले ही बढ़ रहा है, लेकिन यह भी सच है कि गांवों की तसवीर अभी कम से कम वैसी नहीं हो पाई है, जिस स्तर पर शहरी तसवीर है।

गांवों का समृद्ध होना जरूरी है। हाल के दिनों में जनसंख्या को बढ़ाने और न बढ़ाने को लेकर सियासी तौर पर अपने-अपने तर्क दिए जा रहे हैं। इन तर्कों के अपने आधार हो सकते हैं। लेकिन इससे शायद ही कोई इनकार करेगा कि भारत के शहरों की सांस अगर फूल रही है तो इसकी बड़ी वजह उनकी ओर बेतहाशा हो रहा पलायन और उस बड़ी जनसंख्या के लिए इस्तेमाल हो रहे उपभोक्ता वस्तुओं का बड़ा योगदान है। भारत में आबादी बढ़ाने की जगह आबादी के समन्वित और संतुलित वितरण की जरूरत ज्यादा है। ग्रामीण इलाकों में आबादी को रोकने की कोशिश होनी चाहिए। ग्रामीण आबादी को बुनियादी शिक्षा और रोजगार गांवों या उसके आसपास ही उपलब्ध कराने की नीतियों पर आगे बढ़ना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो निश्चित तौर पर आबादी को संतुलित किया जा सकेगा। तब गांव आबादी विहीन नहीं होंगे और शहरों पर आबादी का असंतुलित बोझ नहीं बढ़ेगा।

गांवों में हो रही खपत और खर्च को लेकर आ रहे आंकड़ों का पहला असर यही होना चाहिए कि गांवों में आबादी रूके। लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। ग्रामीण इलाके में बढ़ते खर्च से अव्वल तो गांवों में रोजगार के साधन बढ़ने चाहिए। लेकिन इस दिशा में ठोस बदलाव होते नजर नहीं आ रहे। बेशक आज आजादी के बाद के दौर की तरह के बदहाल गांव नहीं हैं। बेशक शहरों जितना उसे बिजली नहीं मिलती, लेकिन पहले की तुलना में अब गांवों को भी बिजली ज्यादा मिल रही है। गांवों में भी उपभोक्ता वस्तुएं पहुंची हैं। इससे बेशक पारंपरिक संस्कृति चोट भले ही पहुंची हो। यह भी सच है कि ग्रामीण विकास और दूसरी कल्याण योजनाओं के जरिये गांवों में केंद्रीय और राज्य सरकारों की ओर से पैसा जा रहा है। लेकिन यह भी सच है कि उस पैसे का एक बड़ा हिस्सा जमीनी स्तर पर खर्च होने की बजाय नौकरशाही और राजनीतिक रिश्वत के रूप में शहरी इलाकों में ही रूक रहा है और वहीं निवेशित हो रहा है। इस लिहाज से देखें तो ग्रामीण इलाके में जैसी समृद्धि दिखनी चाहिए, कम से कम जमीनी स्तर पर वैसी समृद्धि नहीं है। गांवों का जैसा रूप होना चाहिए, वैसा नहीं है। इसलिए सिर्फ घरेलू खर्च के जरिये ही गांवों की खुशहाली और समृद्धि की खोज करना उचित नहीं होगा। यह तभी होगा, जब गांवों की खुशहाली और समृद्धि मापने के लिए समन्वित और समावेशी मूल्यांकन प्रणाली अपनाएंगे, जिसमें यह भी देखा जाएगा कि कितनी ग्रामीण आबादी को मजबूरी में गांव पीछे छोड़ना पड़ा है और कितनी आबादी गांव लौट रही है। गांवों के लिए ऐसी समन्वित नीतियां तैयार करना और उन्हें लागू करना होगा, जिनके जरिए परंपरा भी बची रहे, संस्कृति की धारा भी अजस्र बनी रहे, समृद्धि भी आए और गांवों को शहरों का मोहताज नहीं होना पड़े, जैसा महात्मा गांधी चाहते थे।

# बजट में नया आयकर विधेयक पेश करने की तैयारी

जल्द ही आम बजट 2025 पेश किया जाएगा। देश के लोगों में बजट घोषणाओं को लेकर उत्सुकता बनी हुई है। आम आदमी, व्यापार जगत, इंडस्ट्री और वृहत समाज को इससे बहुत उम्मीदें होती हैं। देश की आजादी के साथ 26 नवंबर, 1947 को भारत के पहले वित्तमंत्री आरके शानमुखम चेट्टी द्वारा शुरू किया गया यह सफर निर्बाध तरीके से निर्मला सीतारमण तक चला आ रहा है। यह केंद्रीय बजट एक अप्रैल से शुरू होकर अगले साल 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए देश की वित्तीय योजना को तय करेगा। सरकार 2025 के बजट में नया आयकर विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब है कि देश के 64 साल पुराने आयकर कानून में बदलाव हो सकता है। नए विधेयक का लक्ष्य मौजूदा कर नियमों को सरल बनाना, उन्हें समझना आसान बनाना और दस्तावेजों के आकार को लगभग 60 फीसदी तक कम करना है। जहां तक देश की आर्थिक स्थिति का सवाल है तो मौजूदा वित्त वर्ष के लिए पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक, जीडीपी ग्रोथ 6.4 फीसदी पर आती दिख रही है। इसको और गति चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उत्पादन 5.3 फीसदी ही बढ़ेगा, जो पिछले वित्त वर्ष में 9.9 फीसदी बढ़ा था। सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ 5.8 फीसदी रहने का अनुमान है, जो सालभर पहले 6.4 फीसदी थी। फाइनैंशल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सेगमेंट की ग्रोथ 8.4 फीसदी के मुकाबले 7.3 फीसदी रहने का अनुमान है। पहला सुझाव है कि बजट 2025 में सैलरी क्लास को राहत देने के लिए यूनियन बजट में स्टैंडर्ड कटौती बढ़ाने का ऐलान किया जाना बेहतर होगा। वर्ष 2024-25 के यूनियन बजट में वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स की नई रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने का ऐलान किया था।

लंबे समय से मिडिल क्लास इनकम टैक्स में छूट का दायरा बढ़ने की उम्मीद कर रहा है। बजट 2025 में मिडिल क्लास की यह उम्मीद सरकार पूरी कर सकती है। सुझाव है कि इस बार किसान सम्मान निधि की रकम बढ़ा देनी चाहिए। बजट 2024 में इसका अनुमान लगाया गया था। 2019 में पहली बार पीएम किसान सम्मान निधि का ऐलान किया गया था। उसके बाद से इसकी रकम नहीं बढ़ाई गई है। फिलहाल इस स्कीम के तहत किसानों को हर साल 6000 रुपए मिलते हैं। सरकार 2000-2000 रुपए की तीन किस्तों में यह पैसा सीधे किसानों के अकाउंट में ट्रांसफर करती है। इससे किसान राहत महसूस करेंगे। काफी लोग आशा करते हैं कि सरकार को बजट 2025 में मिडिल क्लास के लिए टैक्स छूट बढ़ा देनी चाहिए। सरकार ने सबसे पहले 2022 में इनकम टैक्स की नई रिजीम का ऐलान किया था। उसके बाद से लगातार ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा टैक्सपेयर्स नए टैक्स रिजीम को चुनें। इसी तरह से सरकार ने कैपिटल गेंस टैक्स के नियमों में बजट 2024 में बदलाव किया था। इसे और आसान बनाए जाने की जरूरत है। सुपर रिच यानी अधिक अमीर लोगों पर 2 फीसदी अतिरिक्त टैक्स लगाने का सुझाव दिया है। इस पैसे का इस्तेमाल सोशल सिक्योरिटी बेनेफिट्स शुरू करने के लिए किया जा सकता है। बेहतर हो कि प्रवासी मजदूरों के लिए एक अलग वेलफेयर बोर्ड बनाया जाए। साथ ही वन राशन वन नेशन स्कीम के तहत कंस्ट्रक्शन से जुड़े मजदूरों का भी राशन कार्ड बनाने की मांग की गई है। देश में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं महंगी होती जा रही हैं। बजट 2025 में इसको लेकर राहत की उम्मीद है। देखें और जांचें तो भारत का स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र रोजगार और राजस्व के मामले में सबसे बड़े क्षेत्रों में से एक है। सरकार को स्वास्थ्य सेवाओं पर लगने वाले इनपुट जीएसटी को कम करना चाहिए। इसके साथ ही, बीमा कंपनियों की क्लेम प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है। विदित हो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के बजट में वृद्धि और निजी क्षेत्र को सहयोग देने से लोगों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा सकता है। खास तौर पर उन इलाकों में बुनियादी ढांचे को सुधारने की जरूरत है जहां स्वास्थ्य सेवाएं अभी तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाई हैं।

बजट 2025 भारत की शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने और इसे विश्व स्तरीय बनाने के लिए एक सुनहरा अवसर है। डिजिटल शिक्षा, शिक्षक प्रशिक्षण और कौशल विकास पर जोर देकर सरकार युवाओं को एक मजबूत और कुशल कार्यबल में बदल सकती है। यह न केवल शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, बल्कि भारत की आर्थिक वृद्धि में भी योगदान देगा। 2025-26 के लिए पेश होने वाले सालाना आम बजट में देश के विद्यार्थियों, शोधार्थियों, शिक्षकों और जुड़े कर्मचारियों की भी उम्मीदें बंधी हैं। हालांकि, सरकार ने शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए पिछले सालों में लगातार बजट बढ़ाया है। 2024 में इस क्षेत्र को 1.48 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिसमें से सबसे अधिक 73498 करोड़ रुपए स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को दिए गए। इसके बावजूद, बजट में शिक्षा क्षेत्र को जीडीपी का केवल 4 फीसदी रकम ही आवंटित की जाती है, जबकि अमेरिका, कनाडा, जापान और जर्मनी जैसे विकसित देश 4.8 से 5.5 फीसदी तक खर्च करते हैं। इसमें वृद्धि वांछित है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले कुछ वर्षों में शिक्षा और उच्च शिक्षा के लिए बजट आवंटन में वृद्धि हुई है। हालांकि, उभरते हुए रोजगार क्षेत्र और डिजिटल युग की मांगों को पूरा करने के लिए आवंटन को और बढ़ाने की आवश्यकता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के कार्यान्वयन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

# आत्मिक ज्ञान प्राप्त होने पर ही मनुष्य का जन्म सफल होता है - विष्णु देव चैतन्य जी महाराज

## क्रोध एक ऐसा लक्षण है जो मानव जीवन को बर्बाद कर देता है, यदि हमें ज्ञान प्राप्त होगा तो हम क्रोध पर भी अंकुश कर सकते हैं : विष्णु देव चैतन्य जी महाराज

**गौरव सिंघल । सिटी चीफ (उप्र)** सहारनपुर (नागल)। श्री कृष्ण देव चैतन्य योग आश्रम राजपुरा में मौनी अमावस्या के उपलक्ष में आयोजित यज्ञ उपरांत प्रवचन करते हुए श्रद्धेय विष्णु देव चैतन्य जी महाराज ने कहा कि आत्मिक ज्ञान प्राप्त होने पर ही मनुष्य का जन्म सफल होता है। श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि क्रोध एक ऐसा लक्षण है जो मानव जीवन को बर्बाद कर देता है, यदि हमें ज्ञान प्राप्त होगा तो हम क्रोध पर भी अंकुश कर सकते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें अपने माता-पिता एवं गुरुजनों का आदर करना होगा, यहां यह भी आवश्यक है कि माता भी विदुषी हो, धर्माचार्य हो तभी वह अपनी संतान को धर्म के मार्ग की ओर अग्रसर कर सकती है। इसी तरह पिता भी

धार्मिक तथा परोपकारी हो, ऐसे में जब किसी अच्छे गुरु का सानिध्य मिलता है तो बालक ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर होता है। निरंतर प्रयास से वह ज्ञानवान बन जाता है। उन्होंने कहा कि नित्य कर्म से ही ज्ञान का बोध होता है। आज वर्तमान में हर व्यक्ति पैसे के पीछे अंधा होकर दौड़ लगा रहा है जबकि इससे कल्याण होने वाला नहीं है। धर्म के अनुकूल कर्म करते हुए जो व्यक्ति अपने अपने परिवार का पालन पोषण करता है उसे ही सच्चा सुख प्राप्त होता है। उन्होंने कहा की किसी भी कार्य करने से पहले उसके बारे में जान लेना आवश्यक है यदि हमें उसके बारे में पूर्ण जानकारी होगी तो हम वह कार्य सहित प्रकार से कर सकते है। उन्होंने कहा कि आवेश में आकर अथवा क्रोध में व्यक्ति को उचित अनुचित का बोध नहीं रहता इस दौरान उससे जो कार्य होता है उसका परिणाम सर्वदा गलत ही होता है। आचार्य आत्मदेव जी महाराज ने कहा कि यज्ञ से बढ़कर कोई अन्य पुण्य कार्य नहीं है, यज्ञ कर्म से देवता प्रसन्न होते हैं जो मानव का जीवन सुखमय बनाने का आशीर्वाद देते हैं। यज्ञ में सैकड़ो श्रद्धालुओं ने आहुति देकर पुण्य कमाया। इस अवसर पर मुख्य रूप से आशीष अग्रवाल, सत्य ऐरन, अजय अग्रवाल, सत्य प्रकाश, रमेश कुमार आदि उपस्थित रहे।

# जिलाधिकारी ने की सामाजिक कल्याण से संबंधित योजनाओं की समीक्षा

## छात्रवृत्ति आवेदन फॉरवर्ड न करने वाले विद्यालयों के खिलाफ नोटिस जारी करने के निर्देश

**गौरव सिंघल । सिटी चीफ (उप्र)** सहारनपुर, जिलाधिकारी मनीष बंसल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में समाज कल्याण, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक कल्याण, दिव्यांगजन एवं प्रोबेशन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न लाभार्थीपरक योजनाओं की समीक्षा की गयी। बैठक में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति, दिव्यांग भरण पोषण पेंशन योजना, सहायक उपकरण योजना, विवाह प्रोत्साहन पुरूस्कार योजना, दुकान निर्माण एवं संचालन योजना, विशेष विद्यालयों का संचालन, निराश्रित महिला पेंशन, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना कोविड एवं सामान्य, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ, स्पॉन्सरशिप योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, एकीकृत योजना, स्वच्छकार विमुक्ति पुनर्वास योजना आदि योजनाओं की प्रगति की बारीकी से जानकारी ली। डीएम मनीष बंसल ने निर्देश दिए कि जनपद में कोई भी पात्र व्यक्ति पेंशन योजना से वंचित न रहे। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी खंड विकास अधिकारी सप्ताह में कम से कम एक गांव में जाकर चौपाल के माध्यम से पेंशन एवं अन्य लाभार्थीपरक योजनाओं के लाभार्थियों की सूची पढ़ी जाए। जिससे पात्रों का सत्यापन तेजी से किया जा सके। उन्होंने निर्देश दिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में शादी कराने वाले सभी जोडों का मैरिज रजिस्ट्रेशन कराया जाए।

सभी जोड़ो की पत्रावलियां तैयार कर तत्काल स्वीकृति लें और 31 जनवरी तक लाभार्थियों को भुगतान कराएं। उन्होंने कहा कि सभी खंड विकास अधिकारी प्रमाण पत्र दें कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में किए गए कार्यक्रमों में व्यवस्थाओं में कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में होने वाले सामूहिक विवाह के लिए टेंडर सहित सभी प्रक्रियाएं समय से पूर्ण कर ली जाएं। आवेदनों का सत्यापन समय से पूर्ण हो। डीएम मनीष बंसल ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में लंबित 467 आवेदनों को 31 जनवरी तक निस्तारित कराने के निर्देश दिए। पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति में जिन स्कूल और कॉलेजों द्वारा पात्र बच्चों के फॉर्म फॉरवर्ड नहीं किए गए हैं, उनके प्रधानाचार्य या नोडल को नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण प्राप्त करें। जनपद में समाज कल्याण द्वारा संचालित 04 छात्रावासों का संबंधित उपजिलाधिकारी 01 सप्ताह में निरीक्षण कर व्यवस्थाओं एवं व्यय संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। राजकीय आश्रम पद्धति के विद्यालयों में रिक्त सीटों पर ईंट भट्टों पर काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों का प्रवेश कराएं। डीएम मनीष बंसल ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना में लंबित आवेदनों को 30 जनवरी तक निस्तारित करने के निर्देश दिए। बेटी बचाओं-बेटी पढाओ अभियान के तहत विभिन्न माध्यमों से अधिक से अधिक जनजागरूकता करने के निर्देश दिए। शहर के मुख्य चौराहों पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्लोगन लिखवाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी सुमित राजेश महाजन, डिप्टी कलेक्टर श्वेता पांडेय, पीडी डीआरडीए प्रणय कृष्ण, जिला समाज कल्याण अधिकारी अर्चना, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी दीपिका परिहार, जिला दिव्यांगजन अधिकारी सहित संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे।

# जामिया तिब्बिया देवबंद के प्रबन्धक व निदेशक डा0 अनवर सईद आल इण्डिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किए गए

## यूनानी हल्कों में अपार प्रसन्नता है, डाक्टर अनवर सईद के मनोनयन पर हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी गई

**गौरव सिंघल । सिटी चीफ (उप्र)** देवबंद (सहारनपुर)। जामिया तिब्बिया देवबंद के प्रबन्धक व निदेशक डा0 अनवर सईद को आल इण्डिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस के उत्तर प्रदेश स्टेट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। डा0 अनवर सईद की नियुक्ति पर नगर देवबंद, जामिया तिब्बिया देवबंद तथा तमाम भारतीय चिकित्सा पद्धतियों विशेषतय- यूनानी हल्कों में अपार प्रसन्नता है। आल इण्डिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश पिछले दिनों में एक कमज़ोर संगठन होकर रह गयी थी। इसी कारण इस संगठन के उर्जावान ज़िम्मेदारों विशेषकर डा0 खालिद सिद्दीकी, भूतपूर्व महानिदेशक सी0सी0आर0यू0एम0 ने अलीगढ मुस्लिम विश्वविद्यालय के यूनानी फैकल्टी के सहयोग से एक मीटिंग का आयोजन किया गया। जिसमें यह तय किया गया कि ऐसे लोगों को संगठन की ज़िम्मेदारी दी जाये जो कार्य करने में। सक्षम और जिनका यूनानी पद्धति में विश्वास हो तथा समाज में जिनको विश्वास और आदर की नज़र से देखा जाता हो। इन सूत्रों के परिपेक्ष में डा0 अनवर सईद का चयन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष पद के लिये किया गया। डा0 अनवर सईद ना केवल एक स्थापित और विख्यात यूनानी कालेज के प्रबंधक है अपितु वह दो बार केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद के सदस्य रह चुके हैं तथा दो ही बार आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बि चिकित्सा पद्धति बोर्ड उ0प्र0 (भारतीय चिकित्सा पद्धति बोर्ड) के उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अध्यक्ष मनोनीत किये जा चुके है।

समाजसेवा से लेकर यूनानी तिब्ब के उत्थान के लिये उन्होने जो कार्य किये है पूरा देश उनसे भलीभांति परिचित है। जामिया तिब्बिया देवबंद में आयोजित स्वागत समारोह में भारी कर्तलध्वनि के बीच डा0 अनवर सईद ने कहा कि सदैव मेरा विश्वास पदों में ना होकर रचनात्मक कार्यों को करने में रहा हैं। डा. अनवर सईद ने आल इण्डिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस के ज़िम्मेदारों का आभार जताते हुए कहा कि उन्हें संगठन की ओर से संगठन को नई उर्जा देते हुए इसकी रगों में रचनात्मक उत्थान का रक्त भरने का कार्य करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। जिसे वह पूरा करने का काम करेंगे।

उन्होंने कहा कि यह मेरा सौभाग्य है कि जिस संस्था के अध्यक्ष हकीम सैफुद्दीन तथा सचिव मेरे पिता हकीम शमीम अहमद सईदी जैसे यूनानी महापुरूष रहे हो वहां मुझे कार्य करने का अवसर मिला है। तमाम यूनानी पद्धति के चाहने वाले यह विश्वास रखे कि मेरी अध्यक्षता में यह बरसों पुराना संगठन ना केवल नये आयामों के साथ नज़र आयेगा बल्कि यूनानी चिकित्सा पद्धति तथा इसके पठन-पाठन, यूनानी चिकित्सकों एवं इस पद्धति से जुड़े संस्थानों के लिये हर वो कार्य करने का भरसक प्रयत्न किया जायेगा जो इन सबके लिये हितकारी एवं उत्थान का सहायक हो। डा0 अनवर सईद ने कहा कि वो अपने कार्यकाल में आल इण्डिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस के मरकज़ी विंग के सहयोग के साथ यूनानी पद्धति के सभी पक्षों से सम्पर्क करते हुए उनका सहयोग लेकर कार्य करेंगे तथा इस कर्म में शैक्षणिक संस्थानों से प्रमुख व्यक्तियों का चयन करते हुए एकेडमिक विंग बनायेंगे तथा मेडिकल आफिसर प्रेक्टीशनर रिसर्च विंग आदि बनायेंगे। स्वागत समारोह में जामिया तिब्बिया देवबन्द के प्राचार्य डा0 अनीस अहमद ने मुबारकबाद देते हुए कहा कि यह समय की पुकार है कि एक उर्जावान व्यक्ति ऐसी ज़िम्मेदारियों को संभाले जो यूनानी चिकित्सा पद्धति को उंचाइयों तक ले जा सकें। अस्पताल जामिया तिब्बिया देवबन्द के चिकित्सा अधीक्षक डा0 एहतशाम उल हक ने डा0 अनवर सईद को हार्दिक बधाई देते हुए कहा कि डा0 अनवर सईद का माज़ी इस बात का खुला सबूत है कि वह जिस ज़िम्मेदारी को भी संभालते है उसे सफलता के चरम तक ले जाते है। आल इण्डिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पद पर रहते हुए निश्चित रूप से वह यूनानी तिब्ब के उत्थान का स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे। डा0 अख्तर सईद (सचिव जामिया तिब्बिया देवबंद) ने कहा कि हमारा परिवार हमेशा से यूनानी पद्धति को समर्पित परिवार रहा है। इस परिवार के मेरे बड़े भाई डा0 अनवर सईद तथा आल इण्डिया यूनानी तिब्बी कॉन्फ्रेंस उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त सचिव डा0 मो0 मोहसिन (अध्यक्ष चर्मरोग विभाग फैकल्टी आफ यूनानी मेडिसिन ए0एम0यू0) तथा अजमल खान तिब्बिया कालेज के उर्जावान प्राचार्य डा0 बदरुद्दुजा खान जो इस संस्था की कोओरडिनेशन कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष सब मिलकर यूनानी तरीका-ए-इलाज को नई तरक्क़ीया अता करेंगे। डा0 फसीह सिद्दीकी (उप चिकित्साधीक्षक), डा0 नासिर अली खान, डा0 आज़म उसमानी, डा0 निकहत सज्जाद, डा0 जावेद आलम, डा0 मुज़म्मील, डा0 मो0 जाफर, डा0 शाईस्ता परवीन, डा0 फुरकान डा0 मो0 आसिफ, डा0 मुमताज जहॉ, डा0 अज़ीज़, डा0 संजय शर्मा, डा0 नवाज़ देवबंदी, असद जमाल फैज़ी, जमशेद अनवर, दानिश उस्मानी, शिबली इकबाल आबिद, मो0 जावेद, निशांत उस्मानी आदि ने डाक्टर अनवर सईद के मनोनयन पर हर्ष व्यक्त करते हुए इस चयन पर उनको हार्दिक बधाई दी।

### नारायणपुर पुलिस को मिली सफलता

# सर्चिंग अभियान दौरान आईईडी विस्फोट कर फायरिंग की घटना में संलिप्त तीन माओवादियों को पकड़ा

**गणेश वैष्णव। सिटी चीफ (छग) नारायणपुर,** वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में नारायणपुर पुलिस के द्वारा एक ओर नक्सल विरोधी माड़ बचाव अभियान संचालित कर क्षेत्र में विकास कार्यों में सुरक्षा प्रदान करते हुए अंदरूनी गांव क्षेत्र तक विकास कार्यों को पहुंचाने में गति /सहयोग प्रदान किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में शांति सुरक्षा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए आपराधिक तत्वों पर भी सुक्ष्म निगाह रखकर उनके विरूद्ध कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।इसी कड़ी में 17 अक्टूबर 2024 को नक्सल विरोधी अभियान के दौरान कोडलियार के जंगल पहाड़ी में सुरक्षा बलों पर सर्चिंग दौरान फायरिंग की घटना में संलिप्त रहे 03 माओवादियों को पकड़ने में नारायणपुर पुलिस को सफलता मिली है। ज्ञात हो कि थाना कोहकामेटा क्षेत्रान्तर्गत 17 अक्टूबर 2024 को डीआरजी, एसटीएफ एवं आईटीबीपी, बीएसएफ की संयुक्त टीम नक्सल विरोधी अभियान पर ग्राम धुरबेड़ा, गुमरका, कोडलियार एवं आसपास क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति की आसूचना पर रवाना हुए थे कि कोडलियार जंगल पहाड़ सर्चिंग दौरान गिरफ्तार माओवादी- आयतु राम उसेण्डी, धोबा वड़दा एवं धोबा राम द्वारा अपने अन्य नक्सली साथियों के साथ मिलकर सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने एवं हथियार लुटने के नीयत से फायरिंग कर घटना को अंजाम दिया गया। उक्त घटना में आईटीबीपी के आर. पवार अमर शमराव एवं आर. के.के. राजेश शहीद हुए थे और आर. 693 अनिल कुंजाम व बस्तर फॉईटर आर. 1058 अरविंद सर्पे घायल थे। उक्त घटना पर थाना कोहकामेटा में मामला दर्ज किया जाकर अनुसंधान में लिया गया। घटना के बाद से उक्त तीनों आरोपी सकूनत से फरार हो गये थे, जिसे कोडलियार क्षेत्र में किसी अन्य घटना को अंजाम देने के फिराक घुम रहे थे जिसे सुरक्षा बलों द्वारा सर्चिंग के दौरान घेराबंदी कर हिरासत में लेकर मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ किया गया जिन्होंने उक्त घटना में शामिल रहना बताये जाने एवं अपराध कबूल करने पर दिनांक 28.01.2025 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।

**गिरफ्तार आरोपी** 01. आयतु राम उसेण्डी पिता मालू उसेण्डी उम्र 28 वर्ष, जाति माड़िया ग्राम कोडलियार (मीचिंगपारा) थाना कोहकामेटा जिला नारायणपुर (छ.ग.)।

02. धोबा वड़दा पिता बोडगा वड़दा उम्र 28 वर्ष, ग्राम कोडलियार (मीचिंगपारा) थाना कोहकामेटा जिला नारायणपुर (छ.ग.)।

03. धोबा वड़दा पिता गोरे वड़दा उम्र 27 वर्ष, ग्राम कोडलियार (मीचिंगपारा) थाना कोहकामेटा जिला नारायणपुर (छ.ग.)।

**आपराधिक प्रकरण:-** थाना कोहकामेटा अपराध क्रमांक-13/2024 धारा 191(2), 191(3), 190, 61(2), 111(2)(ख), 103 बीएनएस 25, 27 आर्म्स एक्ट 4, 5 वि.प.अधि. 10, 13(1), 16, 20, 38(2), 39(2) विधि विरूद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम।

### कटनी में दर्दनाक हादसा

# कुंभ से लौट रही कार ऑयल टैंकर से टकराई, चार घायल

***सुनील यादव । सिटी चीफ*** *कटनी, कटनी जिले के कुठला थाना क्षेत्र इंद्रा नगर नेशनल हाइवे पर प्रयागराज कुंभ से लौट रही एक कार ऑयल टैंकर से जोरदार भिड़ंत हो गई इस घटना में कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई वही कार में सवार तीन महिआओ समेत कार ड्राइवर घायल हुए है। मौके पर पहुंचे ट्रैफिक थाना प्रभारी राहुल पांडे ने बताया कि कार सवार सभी घायल हैदराबाद निवासी है जो प्रयागराज से हैदराबाद इनोवा कार से*

*लौट रहे थे तभी कटनी जिले के इंद्रा नगर नेशनल हाइवे पर एक मैहर कि तरफ जा रहा टैंकर वन-वे होने के चलते अचानक सामने आ गया और दोनों की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में इनोवा में सवार चार लोग हुए घायल हुए है जिनका नाम नागरानी, शारदा, प्रवीणा और कार सवार मोहम्मद आरिफ़ अस्पताल भेजा है जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। जिसमे से दो लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है।*

*है।इसकी सूचना मिलते ही।मौके पर पहुंचे ट्रैफिक थाना प्रभारी राहुल पांडे ने इस दुर्घटना में कार में फंसे ड्राइवर आरिफ़ खान को जेसीबी की सहायता से बाहर निकलवा चारों घायलों को जिला*

# जमीन पर कब्जा करने के लिए दबंग कर रहे परेशान,कलेक्टर एसपी को दिया आवेदन

## आयुक्त सागर संभाग से जीत चुके फिर भी दबंग कर रहे परेशान

**धीरज कुमार अहीरवाल । सिटी चीफ**

दमोह, ताहिर नबी उम्र 38 वर्ष पिता स्वर्गीय गुलाम नबी शहर के बजरिया वार्ड नंबर 7 साथ में रहते हैं उनकी एक पुस्तैनी जमीन है जिन्हें उनके पिता ने खरीदी थी। उनकी जमीन का खसरा नंबर 1301/16 रकवा 0.014 हेक्टेयर की भूमि है जिसका प्रकरण न्यायालय आयुक्त सागर संभाग अपील क्रमांक 257/ अपील /अ 70/2021 22 चल रहा था जो दिनांक 24/12/24 को हम जीत गए।लेकिन अब मुबारिक खान द्वारा उन्हें परेशान किया जा रहा है कि यह जमीन खाली कर दो नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत गलत किया जाएगा जिसका आवेदन मैंने दमोह कलेक्टर एवं दमोह एसपी को दिया है ताहिर ने बताया कि वह एक मजदूर है और मजदूर करने के लिए कभी-कभी वह दमोह से बाहर भी जाता है उसके परिवार में छोटे-छोटे बच्चे हैं जो डर के साये में रहते हैं आए दिन मुबारक खान और उनके सहयोगी उनके घर जाकर गाली गलौज करते हैं डराते धमकाते हैं, जिससे मैं बहुत परेशान हो गया हूं और शासन से सुरक्षा की गुहार लगाई है। मैने इसके लिए दमोह कलेक्टर,दमोह पुलिस अधीक्षक को आवेदन दिया है।

# संभाग स्तरीय साफ्टबॉल प्रतियोगिता में बीकेएसएन कॉलेज रहा विजेता

**भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ** शाजापुर, प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस बीकेएसएन गवर्नमेंट कॉलेज शाजापुर का संभाग स्तरीय साफ्टबॉल पुरूष प्रतियोगिता का आयोजन उत्कृष्ट खेल मैदान शाजापुर में किया गया, जिसमें उज्जैन संभाग के 08 महाविद्यालयों ने भागीदारी की। कार्यकम के मुख्य अतिथि महाविद्यालयीन जनभागीदारी अध्यक्ष विपुल कसेरा एवं भाजपा जिला मीडिया प्रभारी विजय जोशी थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉ बीएस विभूति ने की। शुभारंभ बजरंग बली के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्जवलन कर किया गया। कार्यक्रम के समापन पर खेल युवा एवं कल्याण विभाग के जिला खेल अधिकारी रविन्द्र हार्डिया ने विजेता एवं उपविजेता टीमों को ट्रॉफी एवं प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। बीकेएसएन कालेज की टीम विजेता रही। संचालन डॉ दिनेश निंगवाल क्रीडा प्रभारी ने किया। इस अवसर पर महाविद्यालय से डॉ वीपी मीणा, डॉ आरसी चौहान, डॉ बीके सोलंकी, ललित गोवा, क्रीड़ा अधिकारी अभय भौसले, दिनेश धनगर, देवेन्द्र कुभंकार, डॉ आयुष त्रिवेदी, डॉ अंकश सुराह, रफरी गिरीश सोनी, मुकेश गुर्जर, पंकज पारछे, अरूण गवली, दीपेश यादव उपस्थित रहे। आभार क्रीड़ा अधिकारी डॉ सूरज जाट ने माना।

# ग्रामीण विकास मंत्रालय की झाँकी में दिखी लखपति दीदी योजना की झलक

## बालाघाट जिले से भारत सरकार की ओर से विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुई साधना अवधिया और संजू नगपुरे

**लकेश पंचेश्वर । सिटी चीफ**
**लालबर्रा,** 76वें गणतंत्र दिवस परेड में ग्रामीण विकास मंत्रालय की झांकी ने कर्तव्य पथ पर लखपति दीदी योजना का भव्य चित्रण किया। इस योजना का लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के लिए एक लाख रुपये की न्यूनतम आय सुनिश्चित करना है झांकी के सामने नोटो की गड्डी पकड़े लखपति दीदी की एक विशाल प्रतिमा लगी थी, जो उनकी वित्तीय आत्मनिर्भरता का प्रतीक है वंही बुनाई, हस्तशिल्प और कृषि जैसी विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में शामिल महिलाओं को भी इस झांकी में दर्शाया गया झांकी में किताबें पकड़े लड़कियों और कंप्यूटर का इस्तेमाल करती महिलाओं को भी चित्रित किया गया, जो कौशल विकास और आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुकूलन के माध्यम से आत्मनिर्भरता की ओर उनकी यात्रा का प्रतीक है ग्रामीण भारत से संबंधित रूपांकनों जैसे मिट्टी के बर्तन, स्थानीय शिल्प और वनस्पतियां झांकी का हिस्सा थीं ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, 1.15 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों की सदस्य हैं जो एक लाख रुपये से अधिक की वार्षिक घरेलू आय वाली 'लखपति दीदी' बन गई हैं अब तक, 10 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाओं को 91.8 लाख स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया है बालाघाट जिले से साधना अवधिया और संजू नगपुरे गणतंत्र दिवस पर दिल्ली के परेड मैदान में विशेष अतिथि हुई शामिल ,,,, जिले के लिए गर्व की बात है महिलाएं आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह से जुड़कर नए आयाम गढ रही हैं 76वें गणतंत्र दिवस पर प्रदेश के 11 जिलों की 15 महिलाएं दिल्ली के परेड मैदान में बतौर विशेष अतिथि

के रूप में शामिल हुई इनमें से 03 महिलाएं बालाघाट जिले की भी शामिल रही बालाघाट जनपद के ग्राम कोहकाडिबर निवासी संजू श्रवण नगपुरे व ग्राम गोंगलई निवासी प्रमिला देवराम लिल्हारे, लालबर्रा जनपद से ग्राम अमोली निवासी साधना मुकेश अवधिया ने समूह से जुड़ने के बाद उत्कृष्ट कार्य जवाबदारी के साथ पुरे किये हैं। सनद रहे कि जिले में 17 हजार समूहों में डेढ़ लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। जिनमें से 02 महिलाओं का चयन हुआ वंही इन महिलाओ ने परेड में शामिल होकर बालाघाट जिले का प्रतिनिधित्व भी किया मीडिया से जानकारी साँझा करते हुए सीनियर सीआरपी संजू नगपुरे ने बताया कि ह्न वर्ष 2017 में वह समूह से जुड़ने के बाद वाशिंग पाउडर, फिनायल, बर्तन वाश तथा हार्पिक बनाने का कार्य किया, इसके बाद महिलाओं को समूह से जोड़ना शुरु किया और फिर ड्रोन पायलट बनने का मौका मिला, जिससे उसने विभागीय अधिकारी के निर्देश अनुसार इंदौर में जाकर पांच दिवसीय प्रशिक्षण लिया संजू श्रवण नगपुरे का कहना है कि 1 वर्ष के भीतर लगभग 30 एकड़ खेती में ड्रोन चलाकर कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव किया है?, इसके साथ ही 3 महिलाओं को ड्रोन चलाने का प्रशिक्षण भी दिया। वह अभी 1300 महिलाओं की प्रमुख होकर उनका नेतृत्व कर रही हैं, इस वर्ष पहला ऐसा अवसर है कि दिल्ली गए और परेड में विशेष अतिथि शामिल हुए आगे बताया कि गरीब, मध्यम परिवार की महिलाओं को इस समूह से जोड़ा जाता है। पशुपालन, कृषि व अन्य भी व्यवसाय के लिए शासन द्वारा प्रोत्साहित कर और कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ताकि महिलाएं रोजगार कर सके और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। महिलाओं को व्यवसाय में आगे बढ़ाने के बताती हैं तरीके- साधना मुकेश अवधिया ने बताया कि वर्ष 2016 में समूह से जुड़े हैं वह मॉडल सीएलएफ मातृधाम लालबर्रा में एनआईटीपी प्रोजेक्टर बीडीएसपी के पद पर कार्यरत हैं, उनके समूह में 19 महिलाएं हैं, जिन्हें व्यवसाय करने के लिए पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, तो दिलवाने में मदद करती हैं। व्यवसाय किस तरह से करना है और उसे आगे बढ़ाने के तौर तरीके समझाना होता है, हर माह व्यवसाय में बढ़ोत्तरी हो यह प्रयास हमेशा रहता है। समूह की महिलाओं की ओर से तैयार किए गए उत्पाद को सही बाजार मिले इसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करना मुख्य भूमिका है। साधना अवधिया ने कहा कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली के परेड मैदान में विशेष अतिथि शामिल हुई उनके लिए यह सुनहरा पल है। जिले के लिए भी गर्व की बात है कि जिले से महिलाएं राजधानी में पहुंची वंही भारत रत्न सी.सुब्रमणियम ऑडीटोरियम पूसा नई दिल्ली के सभाग्रह में सशक्त समुदाय सशक्त लखपती दीदी ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अभिनन्दन समाहरोह में भी शामिल हुई जंहा केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी दीदियों का स्वागत, अभिनंदन और सभा में उपस्थित विभिन्न राज्यों से आई सभी दीदियों कों सम्बोधित भी किया साथ ही अपने निवास स्थान 12 सफदरगंज रोड दिल्ली में सहभोज में सभी दीदियों के साथ शामिल रहे

# नारायणपुर में कुतुल एरिया कमेटी के 29 माओवादियों ने किया एक साथ आत्मसमर्पण

**गणेश वैष्णव । सिटी चीफ (छग)** नारायणपुर, जिला नारायणपुर क्षेत्र में चलाये जा रहे आत्मसमर्पण नीति ''माड़ बचाओ अभियान'' को ऐतिहासिक सफलता मिली है। कुतुल एरिया कमेटी अन्तर्गत कार्यरत 29 माओवादियों नें किये बिना हथियार के नक्सल करूर विचारधारा से तंग आकर एक साथ आत्मसमर्पण कर दिया है। इनमें जनताना सरकार, मिलिशिया , सीएनएम, कृषि सदस्य, पंचायत सरकार अध्यक्ष व सदस्य शामिल हैं । आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को प्रोत्साहन राशि 25 हजार का चेक प्रदाय किया गया है एवं उन्हें नक्सल उन्मूलन नीति के तहत् मिलने वाली सभी प्रकार की सुविधाएं दिलायी जायेंगीं। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों में 22 पुरूष व 0। महिला माओवादी शामिल हैं जो क्षेत्र में सक्रिय रूप से माओवादियों के लिए काम करते थे। इस प्रकार से लगातार माओवादियों के हो रहे आत्मसमर्पण से नक्सलियों को बड़ा झटका लगा है। महानिरीक्षक पुलिस बस्तर रेंज जगदलपुर सुन्दरराज पी. (भा.पु.से.), पुलिस उप महानिरीक्षक कांकेर रेंज अमित तुकाराम काम्बले (भा.पु.से.) के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक नारायणपुर प्रभात कुमार (भा.पु.से.) एवं अति. पुलिस अधीक्षक नारायणपुर रोबिनसन गुड़िया (भा.पु.से.) के निर्देशन में नारायणपुर पुलिस द्वारा माओवादियों के विरूद्ध क्षेत्र में लगातार चलाये जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान और अति संवेदनशील अंदरूनी क्षेत्रों में लगातार कैम्प स्थापित होने से पुलिस के बढ़ते प्रभाव व नक्सलियों की अमानवीय, आधारहीन विचारधारा एवं उनके द्वारा किए जा रहे शोषण, अत्याचार तथा बाहरी नक्सलियों के द्वारा भेदभाव करने तथा स्थानीय आदिवासियों पर होने वाली हिंसा से तंग आकर नक्सल संगठन से 35 माओवादियों के आत्मसमर्पण की यह महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इतनी अधिक संख्या में माओवादियों के आत्मसमर्पण के पीछे माड़ और नारायणपुर जिले में चलाये जा रहे विकास कार्य एवं तेजी से बनती सड़कें हैं जिनसे गांव तक सुविधाएं पहुँच रही हैं जिन्होंने लोगों को प्रभावित किया है। इसके अलावा माओवादी संगठन के विचारों से मोहभंग होना और पनप रही निराशा तथा संगठन के भीतर बढ़ते आंतरिक मतभेद भी आत्मसमर्पण के लिये कारण बताए जा रहे हैं । आने वाले समय में और भी नक्सलियों के संगठन छोड़कर आत्मसमर्पण करने की संभावना है। आत्मसमर्पण कराने में नारायणपुर पुलिस का विशेष योगदान है। इस प्रकार बहुत अधिक संख्या में नक्सलियों का आत्मसर्पण से शीर्ष माओवादी कैडर के लिए बड़ा नुकसान हुआ है। नक्सल मुक्त माड़ बचाव अभियान की कल्पना साकार रूप ले रहा है। आत्मसमर्पण करने वाले माओवादियों ने कहा है कि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़कर स्वच्छंद रूप से सामान्य जीवन जीना चाहते हैं। ग़ौरतलब है कि वर्ष 2024 से अब तक ।1 से अधिक बड़े-छोटे कैडर के माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं। 60 से अधिक माओवादियों मारे जा चुके हैं व 50 से अधिक माओवादियों को गिरफ्तार किया जा चुका है । इसके परिणामस्वरूप माओवादी संगठन कमजोर होते जा रहे हैं और अबूझमाड़ में विकास, सुरक्षा एवं शांति का सपना साकार होता दिख रहा है ।

# सर्व मुस्लिम समाज परिचय सम्मेलन के दूसरे सफल आयोजन पर पदाधिकारियों का किया सम्मान

**भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ** शाजापुर, जिले में दूसरे वर्ष भी आयोजित किए गए सर्व मुस्लिम समाज के युवक-युवती परिचय सम्मेलन के सफल होने पर समिति पदाधिकारियों का समाज के वरिष्ठों ने पुष्पमाला पहनाकर स्वागत-सम्मान किया। मुस्लिम समाज के शादी योग्य बेटे और बेटियों को बेहतर हमसफर तलाशने में मदद करने के उद्देश्य से 2। जनवरी को शाजापुर के हाट मैदान स्थित अपना मैरिज गार्डन में राष्ट्र स्तरीय सर्व मुस्लिम समाज का युवक-युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में बेटियों को निःशुल्क पंजीकृत किया गया था। सम्मेलन में मध्यप्रदेश के अलग-अलग जिलों के साथ ही राजस्थान के मुस्लिम समाज के लडक़ा-लड़कियां और उनके परिजन शामिल हुए थे। लगातार दूसरे वर्ष आयोजित किए गए सम्मेलन के सफल होने पर सम्मेलन समिति के अध्यक्ष शफीक खान, उपाध्यक्ष अमजद खान और कोषाध्यक्ष सलमान खान का समाज के वरिष्ठ याकूब खान, अबसार अहमद खान, जहीर पेंटर के द्वारा पुष्पमाला पहनाकर स्वागत-सम्मान किया गया। साथ ही पदाधिकारियों के कार्य की सराहना करते हुए आगामी दिनों में भी सम्मेलन को निरंतर संचालित किए जाने की बात कही। सम्मान के दौरान समाज के वरिष्ठों ने कहा कि युवा पत्रकारों की पहल बेहद सराहनीय है और यह पहल समाज को आगे ले जाने में अहम भूमिका निभाएगी।

**100 युवक-युवतियों का कराया था परिचय** उल्लेखनीय है कि शाजापुर जिले का दूसरा सर्व मुस्लिम समाज का ऐतिहासिक युवक-युवती परिचय सम्मेलन आयोजित करने का बीड़ा शहर के पत्रकार शफीक खान, अमजद खान और सलमान खान ने उठाया था और 2। जनवरी 25 को हुए सम्मेलन में प्रदेश के अन्य जिलों के 100 युवक-युवतियों ने शामिल होकर अपना परिचय दिया था। सम्मेलन के सफल आयोजन पर जिलेभर में तीनों युवाओं के कार्य की सराहना की जा रही है और समाज के वरिष्ठ उनका सम्मान कर उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं। समाजजनों का कहना है कि समाज हित में इस तरह के आयोजन की लंबे समय से दरकार थी जो पूरी हुई है और कई बेटे-बेटियों को बेहतर रिश्ता मिला है।

# विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को दी राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं प्रवेश प्रक्रिया की जानकारी

**भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ**
शाजापुर, शैक्षणिक सत्र 2025-2026 के लिए कॉलेज चलो अभियान के अंतर्गत बीकेएसएन शासकीय अग्रणी महाविद्यालय शाजापुर के प्राचार्य डॉ बीएस विभूति के नेतृत्व में कॉलेज चलो अभियान के नोडल अधिकारी डॉ अरुण कुमार बोड़ाने, डॉ वीपी मीणा एवं डॉ दिनेश निंगवाल बुधवार को महारानी लक्ष्मीबाई कन्या हायर सैकेंडरी स्कूल शाजापुर में पहुंचे। इस दौरान डॉ बोड़ाने ने विद्यार्थियों को ई-प्रवेश एवं महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रमों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में विद्यार्थियों के लिए बहुत ही हितकारी निर्णय लिए गए हैं, जिससे विद्यार्थी अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। डॉ मीणा ने एनसीसी एवं महाविद्यालय के बारे में जानकारी दी। तत्पश्चात डॉ निंगवाल ने शासन की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं एवं खेलकूद विधाओं के बारे में बताया। इस अवसर पर राजेंद्र नामदेव, राधेश्याम सूर्यवंशी, हेमलता सक्सेना, राधेश्याम सूर्यवंशी, मुकेश दुबे, सरिता मालवीय, भारती शर्मा सहित अनेक छात्राएं एवं उनके अभिभावक उपस्थित थे।

**यहां भी हुआ आयोजन**उच्च शिक्षा विभाग से प्राप्त निर्देशों के परिपालन में किला परिसर स्थित शासकीय कन्या महाविद्यालय शाजापुर द्वारा कॉलेज चलो अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत महाविद्यालय दल द्वारा नगर के हायर सैकेंडरी स्कूलों में अध्ययरत कक्षा 12वीं की छात्राओं को महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। इसी क्रम में शासकीय कन्या महाविद्यालय प्राचार्य डॉ पी मूंदड़ा के निर्देशन में कॉलेज चलो अभियान दल प्रभारी डॉ कपिल जाटव, सदस्य डॉ रितेश महाडिक़, डॉ संदीपकुमारसिंह एवं डॉ ऋचा सक्सेना बस स्टैंड स्थित शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय पहुंचे, जहां कक्षा 12वीं की छात्राओं को प्राध्यापकों द्वारा महाविद्यालय में संचालित विभिन्न पाठ्यक्रमों की जानकारी प्रदान की गई। तत्पश्चात उन्हें महाविद्यालय में उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं जैसे स्वामी विवेकानंद कॅरियर मार्गदर्शन योजना के अंतर्गत रोजगारोन्मुखी सर्टिफिकेट कोर्स, राष्ट्रीय सेवा योजना से समाज विकास में भागीदारी तथा खेल क्षेत्र में रोजगार के अवसर के बारे में बताया। साथ ही महाविद्यालय में शासन द्वारा चलाई जा रही विभिन्न महिला केंद्रित छात्रवृत्तियों एवं योजनाओं की जानकारी दी गई। इस अवसर पर उत्कृष्ट विद्यालय के प्राचार्य पीके मंडलोई, शिक्षक माखनलाल धानुक सहित अन्य शिक्षक एवं विद्यार्थी उपस्थित थे।

# महाकुम्भ का दूसरा अमृत स्नान संपन्न

## मौनी अमावस्या पर सभी 13 अखाड़ों ने सादगी के साथ त्रिवेणी में लगाई पुण्य डुबकी

**रघुवीर सिंह । सिटी चीफ (उ प्र)**
महाकुम्भ नगर, प्रयागराज महाकुम्भ का दूसरा अमृत स्नान पर्व संपन्न हो गया। मौनी अमृत स्नान पर्व पर घटी घटना के बाद अखाड़ों ने संवेदनशीलता दिखाते हुए पहले श्रद्धालुओं को अमृत स्नान करने का अवसर दिया और बाद में सांकेतिक रूप से अमृत स्नान किया।

**मौनी अमावस्या अमृत स्नान पर अखाड़ों ने दिखाई संवेदनशीलता**
**त्रिवेणी** के तट पर लगे आस्था के महाकुम्भ का दूसरा अमृत स्नान पर्व संपन्न हो गया। प्रशासन द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर्व पर शाम 6 बजे तक करोड़ों लोगों ने पुण्य की डुबकी लगाई। महाकुम्भ में घटी घटना के बाद अखाड़ों के संतों ने संवेदनशीलता दिखाई। यह पहला मौका था जब साधु-संतों, नागा संन्यासी और अखाड़ों ने संगम में ऐतिहासिक प्रथम स्नान की प्रतिज्ञा तोड़ दी। परिस्थिति को देखते हुए अखाड़ों ने अपने ब्रह्म मुहूर्त के अमृत स्नान को स्थगित कर दिया और श्रद्धालुओं को पहले स्नान का अवसर दिया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि सर्व सम्मति से सभी अखाड़ों ने निर्णय लिया कि हालात को देखते हुए पहले श्रद्धालुओं को अमृत स्नान का अवसर दिया जाय। स्थिति सामान्य होने पर अखाड़ों ने अपनी भव्य अमृत स्नान की परम्परा का त्याग कर दिया और सांकेतिक रूप से स्नान कर परम्परा का निर्वहन किया।

**शंकराचार्यों ने भी संगम में किया अमृत स्नान**
प्रयागराज महाकुम्भ के दूसरे अमृत स्नान में मौनी अमावस्या पर देश के तीन पीठों के शंकराचार्यों ने भी त्रिवेणी के संगम में डुबकी लगाई। शंकराचार्य ने श्रद्धालुओं से संयम बनाए रखने की अपील की। श्रृंगेरी शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरू शंकराचार्य स्वामी विधु शेखर भारती जी, द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगतगुरू शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी और ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी ने मौनी अमावस्या अमृत स्नान पर्व पर त्रिवेणी संगम में पुण्य की डुबकी लगाई। तीनों पीठ के शंकराचार्य मोटर बोट के माध्यम से त्रिवेणी संगम पहुंचे, जहां पूरे धार्मिक विधि विधान से तीनों ने पुण्य की डुबकी लगाई और देश की जनता के कल्याण के लिए आशीष दिया।

# महाकुंभ में श्रद्धालुओं की ज़िद से बिगड़ी व्यवस्था

## प्रशासन ने संभाला मोर्चा, बड़ा हादसा टला

**रघुवीर सिंह । सिटी चीफ (उ प्र)** महाकुंभ की घटना का कारण बदइंतज़ामी से कहीं ज्यादा श्रद्धालुओं का संगम नोज पर जाकर घंटों रुककर मौनी की सुबह का इंतज़ार, अखाड़ों को देखने के लिए रुकना, वहीं कंबल ओढ़कर बैठना और सोना था। प्रशासन के अनाउंसमेंट को नकार दिया भीड़ ने, जिसमें मेला अधिकारी कह रहे थे कि मौनी अमावस्या का नहान ।.40 श्रद्ध से प्रारंभ हो चुका है । आप जल्द नहाएं और प्रस्थान करें. इस पर पब्लिक की प्रतिक्रिया शून्य थी। तत्पश्चात ट्रैफिक पुलिस ने सारे पीपा पुल बंद कर दिए जिससे और भीड़ न आ जाए । इससे भी जनता नाराज़ हुई और पुलिस से गली गलोच के वीडियो सोशल मीडिया पर आए। पर्यटन के लिहाज से आए बड़ी संख्या में लोग किसी भी असुविधा को लेकर नाराज हो रहे हैं, अखाड़ों के दर्शन की जिद इसका उदाहरण है। बैरक पर खड़ी भीड़ और उस पर चढ़ते लोगों की वजह से वो टूटा । साथ ही यही पब्लिक उल्टी दिशा से आ रहे लोगों वाले रास्ते पर भागने लगे इससे भगदड़ की संघनता और बढ़ी। ग़ज़ब की फुर्ती से इसे प्रशासन ने संभाला।

।0 के करीब एम्बुलेंस दौड़ पड़ी और सभी घायल मेला अस्पताल और कुछ मेडिकल कॉलेज शिफ्ट किए गए। एम्बुलेंस के लिए ग्रीन कॉरिडोर बना वो भी चंद मिनटों में। प्रशासन और अस्पताल का कोऑर्डिनेशन कमाल था जिससे हादसे को संभाला गया और अन्य श्रद्धालुओं को नहाकर लौटने के लिए प्रेरित किया गया। इन सबके बावजूद 70% पब्लिक नहाने के बाद लौटने और हिलने को तैयार नहीं थी । वे अब और आराम से थे क्योंकि पूरा एरिया सील कर दिया गया था। वे सब अखाड़ों, आचार्यों और नागाबाबा के अखाड़ों का स्नान देखना चाहते थे। हार कर अखाड़ों से कहलवाया गया कि वे अपना स्नान स्थगित कर रहे हैं । इस उद्घोष के 3 - 4 घंटों के बाद पूरा संगम नोज सामान्य हो चला था और पीपे के पुल और अन्य सड़कों को पुनः खोल दिया गया। अब स्थिति पूर्णतः कंट्रोल में है। गंगा मैया का शुक्र है बहुत बड़े हादसे की आस में बैठी पिशाची आत्माएं निराश हुई हैं। वर्तमान स्थिति को देखते हुए 10 करोड़ श्रद्धालुओं का स्नान सफलतापूर्वक हो सकेगा ऐसी आशा है। जनता को समझना होगा आज का पर्व साधारण माघ का दिन नहीं है और जिस भी घाट के वे नजदीक हैं स्नान करें और पुण्य कमाएं। संगम नोज पर मात्र 1 से 5 ह्न लोग ही पहुंच कर डुपकी लगा पाएंगे। संगम के तीरे 44 घाट बने हैं कहीं पर भी स्नान करने से वही पुण्य मिलेगा जो संगम पर। अब स्थिति सामान्य है और लोग नहाकर संगम से लौट रहे हैं। ऐसा देखा यह घोषणा हुई कि सभी अखाड़े पूर्ववत शाही स्नान करेंगे। सभी मित्रों से अनुरोध है बिस्तरों में बैठे बैठे टिप्पणी करने वालों, सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भयावह स्थितियों की रिपोर्टिंग और अफवाहों पर भरोसा न करें। अंत में, अनुरोध है प्रशासन के सुझाव और आदेश को मानिए और मेला क्षेत्र को सुव्यवस्थित बनाए रखने में सहयोग कीजिए।

## मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं पर हुई पुष्पवर्षा

# अमृत स्नान पर्व पर सभी घाटों और अखाड़ों पर हेलीकॉप्टर से हुई पुष्पवर्षा

**रघुवीर सिंह । सिटी चीफ (उ प्र)**
महाकुम्भ नगर, महाकुम्भ 2025 के दूसरे अमृत स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर बुधवार को संगम तट पर डुबकी लगाने पहुंचे अखाड़ों के साधु, संतों, नागाओं और श्रद्धालुओं पर योगी सरकार ने हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा कराई। हेलीकॉप्टर से सभी घाटों और अखाड़ों पर स्नान के दौरान श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश की गई। गुलाब की पंखुड़ियों की बारिश देख संगम तट पर मौजूद श्रद्धालुओं ने भी जय श्री राम और हर हर महादेव के नारे लगाए। पुष्प वर्षा के लिए उद्यान विभाग ने 25

क्विंटल गुलाब की पंखुड़ियों की व्यवस्था की थी।

# खराब गेंहू की हुई नीलामी

**भगवान दास बैरागी । सिटी चीफ**
शाजापुर, खराब गेंहू की नीलामी की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार भागीरथ वेयर हाउस ग्राम भदौनी और भागीरथ एग्रो वेयर हाउस एबी रोड में वर्ष 2020-21 से 15 हजार क्विंटल से अधिक गेंहू भंडारित था जो पूरी तरह से खराब हो गया था। मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड ने गेंहू के खराब होने के बाद इसकी नीलामी की प्रक्रिया शुरू की। नीलामी में पंजाब की कंपनी मेसर्स शमशेरसिंह एंड संस ने इस गेंहू को खरीदा। साधु संत और श्रद्धालु बोले- योगी सरकार की सक्रियता ने टाला बड़ा हादसा

**पल-पल की रिपोर्ट लेते रहे सीएम योगी, तड़के ही सरकारी आवास पर बुलाई उच्च स्तरीय बैठक** महाकुम्भ, मौनी अमावस्या पर्व पर बुधवार को महाकुम्भ में और भी बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन योगी सरकार की प्री प्लान्ड तैयारियों और अधिकारियों की सक्रियता ने इसे सीमित कर दिया। महाकुम्भ में विभिन्न साधु संतों और श्रद्धालुओं ने योगी सरकार की व्यवस्थाओं और सुविधाओं को लेकर यह प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि महाकुम्भ में योगी सरकार ने बहुत बेहतर व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन बुधवार को जिस तरह मेले में भीड़ बढ़ी, यह बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि, योगी सरकार और मेला प्रशासन, मेला पुलिस की सजगता और सक्रियता से इस बड़े हादसे को सीमित कर दिया गया। खुद सीएम योगी इस घटना की पल-पल की रिपोर्ट लेते रहे। सुबह घटना की सूचना मिलते ही सीएम योगी ने अधिकारियों से अपडेट लिया और तड़के ही अपने सरकारी आवास पर मुख्य सचिव, प्रमुख

सचिव गृह, डीजीपी, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर के साथ उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

**योगी सरकार की सक्रियता ने सीमित की घटना** श्री पंच दशनाम आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रकाशानंद ने कहा कि महाकुम्भ में अफवाह की वजह से यह घटना घटी है, लेकिन योगी जी की सरकार ने, उनकी पुलिस ने इस घटना पर तुरंत एक्शन लिया जिससे बहुत से लोगों की जान बच गई। जिस तरह की भीड़ थी, ये हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। ये योगी सरकार की व्यवस्था ही थी, यूपी पुलिस का क्विक रिस्पांस ही था, जो बड़ी घटना को सीमित कर दिया गया। इसके लिए योगी सरकार को साधुवाद।

**शासन और प्रशासन ने दिखाई मुस्तैदी** नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष प्रशांत अग्रवाल ने कहा कि मौनी अमावस्या पर्व पर देश और दुनिया से करोड़ो श्रद्धालुओ की भीड़ उमड़ी है। शासन और प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए घटना को नियंत्रित कर लिया। सरकार और व्यवस्था में लगे अधिकारियों की मेहनत से महाकुम्भ का अमृत स्नान शांतिपूर्ण व्यवस्थाओं से संपन्न किया जा रहा। अमृत स्नान पर आए श्रद्धालुओं और संतों से सावधानी रखते हुए अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करता हूं। सभी से सहयोग करने की अपेक्षा के साथ प्रशासन के प्रयासों की सराहना करता हूं।

**प्रत्यक्षदर्शी बोले, योगी सरकार के इंतजाम बेहतर** एक प्रत्यक्षदर्शी के मुताबिक योगी सरकार ने मौनी अमावस्या की फूलप्रूफ प्लानिंग की थी, लेकिन जो घटना घटी उसके लिए काफी हद तक पब्लिक भी जिम्मेदार है। यदि धक्का-मुक्की नहीं होती तो यह घटना नहीं घटती। विपक्ष तो गिद्ध की भूमिका निभा रहा है। गोपालगंज बिहार से आई कुमकुम श्रीवास्तव ने बताया कि महाकुम्भ आकर बहुत अच्छा लगा। योगी सरकार ने अच्छी व्यवस्था की है, लेकिन जो घटना घटी है उसके लिए भारी भीड़ और कुछ लोगों लापरवाही की बड़ी भूमिका है। सरकार तो बार-बार कह रही थी कि जिस स्थान पर आएं वहीं स्नान करें तो फिर संगम नोज पर जाने की क्या आवश्यकता थी।

# ब्राह्मण समाज नवीन कार्यकारिणी का गठन

**बदनावर** बदनावर श्री ब्राह्मण समाज बदनावर की नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ। अध्यक्ष दीपक द्विवेदी ने अपने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए ब्राह्मण समाज सचिव विनोद शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण देव, कोषाध्यक्ष नितिन शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष भूपेंद्र शर्मा, उपाध्यक्ष पार्षद जितेंद्र शर्मा, मनीष शर्मा, सुनील चौधरी, शुभम मोतीलाल शर्मा, मालव राजपुरोहित, गजेंद्र शर्मा, सह सचिव शुभम विजय शर्मा, एवं मीडिया प्रभारी धर्मेंद्र अग्निहोत्री को नियुक्त किया। नव नियुक्त सभी पदाधिकारी का सम्मान समारोह परशुराम वाटिका बड़ी चौपाटी पर रखा गया। जिसमें सभी नवनियुक्त पदाधिकारी को वरिष्ठ सरक्षको द्वारा पुष्पमाला पहनकर स्वागत किया। इसके पूर्व परशुराम जी के मंदिर में पूजन पाठ एवं पुष्पमाला पहनकर समाज जनों ने आशीर्वाद लिया। समाज अध्यक्ष दीपक द्विवेदी ने बताया कि आगामी समय में बदनावर में ब्राह्मण समाज के बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार करने का प्रस्ताव रखा गया है समाज जनों की सहमति के बाद आगामी समय में आयोजन किया जाएगा। ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष प्रजेंद्र भट्ट ने कहा कि नव नियुक्त सभी पदाधिकारी और सदस्य अगर समाज को एकजुट करने का प्रयास करें, तो समाज में एकता, सहयोग और सामूहिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। समाज के सभी पदाधिकारी मिलकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण से काम करें और आपसी मतभेदों को भूलकर समाज के हित में निर्णय लें। इस मौके पर भूतपूर्व सैनिक गोवर्धन लाल शर्मा, भेरूलाल पंड्या, प्रजेंद्र भट्ट, ईश्वर लाल जोशी, मुकेश उपाध्याय, अरुण शर्मा विजय शर्मा सहित बड़ी संख्या में समाज जन उपस्थित थे। उक्त जानकारी मीडिया प्रभारी धर्मेन्द्र अग्निहोत्री ने दी।

# पंचेड आश्रम द्वारा श्रद्धा पूर्वक एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई गई मोनी अमावस्या

पंचेड आश्रम द्वारा वैसे तो प्रत्येक पर्व को बहुत ही भव्य तरीके से एवं श्रद्धा पूर्वक मनाया ही जाता है किंतु अमावस्या का इंतजार जरूरतमंद लोगों एवं भक्तों को विशेष रूप से रहता है। क्योंकि इस दिन लोग आश्रम आकर ईश्वर भक्ति गुरु भक्ति गुरु सेवा के द्वारा अपने पितरों को भी प्रसन्न करते हैं। आज भी आश्रम पर मौनी अमावस्या होने के कारण बहुत बड़ी संख्या में भक्तों का पहुंचना हुआ। जहां सभी ने अपनी मानों कामना पूर्ति के लिए पचेड आश्रम स्थित सिद्ध वृक्ष की परिक्रमाऐं की तत्पश्चात सभी ने समारोह पूर्वक गुरु वंदना एवं प्रार्थना के उपरांत श्री आशा रामायण जी का पाठ ,वीडियो सत्संग, भजन, कीर्तन आदि का लाभ लिया। आश्रम के श्रीमान प्रवीण भाई ने बताया कि महा आरती के उपरांत आज प्रत्येक अमावस्या के अनुसार दरिद्र नारायण लोगों को नगद दक्षिणा वस्त्र, अनाज , नमक के पाउच ,माचिस के पैकेट, एवं सभी को सत साहित्य विशेष ऋषि प्रसाद, लोक कल्याण सेतु, मधुर व्यवहार इत्यादि का वितरण और अंत में सभी को प्रसाद का वितरण किया गया।

# महात्मा गांधी घटियावली में इंडियन ऑयल की सीएसआर पहल

## बालिकाओं के लिए बनाए टायलेट यूनिट का लोकार्पण

**शंभूपुरा ।**महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय घटियावली में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड चित्तौड़गढ़ टर्मिनल ने सीएसआर के तहत बालिकाओं के लिए टायलेट यूनिट का निर्माण करवाया। विद्यालय विकास प्रभारी गणपत आमेरिया ने बताया कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड चित्तौड़गढ़ टर्मिनल ने विद्यालय में बालिकाओं के लिए टायलेट यूनिट का निर्माण करवाया जिसका लोकार्पण इंडियन आयल कारपोरेशन के महाप्रबंधक मनीष चितकारा और चित्तौड़गढ़ टर्मिनल के वरिष्ठ प्रबंधक अत्री अग्रवाल के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुआ। संस्था प्रधान कैलाश चंद्र खटीक की अध्यक्षता में आयोजित हुए कार्यक्रम में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के बंथरा डीपो के एसडीएम दिनेश और सागर डीपो के प्रबंधक अनुराग सैनी अतिविशिष्ट अतिथि थे। जबकि इंडियन ऑयल के जगदीश शर्मा, शशांक जैन और कौशल जागृत विशिष्ट अतिथि थे। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के समस्त अधिकारियों का संस्था प्रधान कैलाश चंद्र खटीक, विद्यालय एसडीएमसी के पीईईओ दीनदयाल नाराणीवाल, उपसरपंच ज्ञानेश्वर पुरी गोस्वामी, आदित्यवीर सिंह शक्तावत, गोपाल कुमावत, रणजीत सिंह शक्तावत, डॉ

इंदू श्रंगी, शिक्षक संघ के प्रमोद गौड़ व वरिष्ठ ग्रामवासियों ने स्वागत अभिनन्दन किया। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के अधिकारियों ने टायलेट यूनिट के लोकार्पण के साथ ही विद्यालय में अशोक के पांच पौधे भी लगाए तथा विद्यालय में आगे भी लगातार सहयोग का आश्वासन दिया तथा कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों को पानी की बोतल भेंट की। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय के हेमलता वैष्णव और गणपत आमेरिया ने संयुक्त रूप से किया।

# तराना विधायक महेश परमार पहुंचे कृष्ण कुंज कॉलोनी मे संगीतमय श्री राम कथा में

तराना– विधायक महेश परमार तराना वार्ड क्रमांक 15 में स्थित कृष्ण कुंज कॉलोनी में साध्वी श्री सुगना बाईसा के कार्यक्रम में अपने साथियों के साथ प्रवचन सुनने पहुंचे यहां पहुंच उन्होंने बताया कि माता रानी के प्रवचन सुन व्यक्ति का मन मुग्ध हो जाता है। विधायक महेश परमार के साथ कार्यक्रम में तराना नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि रुपेश परमार पार्षद पवन बारोड पार्षद सदानंद दीक्षित पार्षद दीपक जनौलिया पूर्व पार्षद दीपक दवे मोहसिन जागीरदार प्रदीप बाजपेई फिरोज पैंथर और भी अनेक साथी मौजूद रहे। इसके अलावा तराना विधायक महेश परमार ने प्रयागराज कुंभ में हुई भगदड़ में मारे गए लोगों के प्रति अपनी शोक संवेदनाएं भी व्यक्त की ।

# शहर के जागरूक युवाओं ने लगाई पुकार कलेक्टर साहब शहर की गंगा बनी प्लास्टिक ओर गन्दगी का गढ़, जरा इधर भी हो ध्यान आकर्षित

**शंभूपुरा।**
अपने गौरवशाली इतिहास और दुर्ग के साथ प्राकृतिक सौंदर्य भी चितौड़गढ़ की पहचान व विरासत है। चित्तौड़ शहर उन गिने चुने शहरों की सूची में शामिल है जहां शहर के बीच से दो नदिया गुजरती है और उनका संगम भी यही होता है। इन नदियो का पवित्र जल शहर के लोगो की पानी की आवश्यकता पूर्ति करता है, एवं कई धर्म के लोग यहाँ पूजा आरती करने भी समय समय पर आते रहते है, लेकिन चित्तौड़ शहर की गंगा %%गंभीरी नदी%% में सैकड़ो टन प्लॉस्टिक प्रवाहित होता नज़र आ रहा है। नदी का किनारा मिट्टी के बजाय प्लास्टिक का गढ़ बन गया है जिससे नदी में फैलते प्लास्टिक प्रदूषण से पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुँच रही है साथ ही नदियो के किनारे और जल निकायों में जलीय जीवन पर इसका असर पड़ रहा है, विशेष बात यह कि यह नदी कलेक्ट्रेट से मात्र 500 मीटर कि दूरी से ही होकर गुजर रही, जहाँ दिन में कई जिला स्तरीय अधिकारी, जिला कलेक्टर सहित सभी जनप्रतिनिधि भी यही से होकर गुजरते है, बावजूद इसके यह अनदेखी का शिकार हो रही है।

बढ़ते प्लास्टिक और इनसे होने वाले प्रदूषण की रोकथाम हेतु शहर के जागरूक युवा दीपक राज़ोरा चीनू, गोविंद ईनानी, हरीश वेद, केशव माहेश्वरी ने ज़िला कलेक्टर चित्तौड़गढ़ का इस ओर ध्यान आकर्षित करने हेतु निवेदन किया।

इस संबंध में दीपक राजोरा ने बताया कि नई पुलिया के पास नदी के किनारे से सटे ईनानी सीटी सेंटर पर आये दिन मनोरंजन, राजनीतिक, सामाजिक संबंधी इवेंट, मेले, कार्यक्रम होते रहते है जहाँ पर उपयोग किया गया सैंकड़ो टन प्लॉस्टिक कचरा सीधे तौर पर नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। इन इवेंट और कार्यक्रम के बाद उक्त जगह पर सैंकड़ो टन प्लास्टिक एकत्रित होता है जिसे गोवंश तो खाते ही है साथ ही साथ उसी कचरे को बाद मे नदी में डाल दिया जाता है। जिससे नदी में पानी से ज्यादा प्लास्टिक कचरा देखने को मिल रहा है। नदी में घुलते इस ज़हर को सरकार और प्रशासन द्वारा अनदेखा किया जा रहा है। एक और जहाँ सरकार द्वारा स्वच्छ भारत अभियान और नमामि गंगे जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे है वही दूसरी ओर इन कार्यक्रमों और योजनाओं का असर शहर की नदी पर नज़र नहीं आ रहा है।

इस संबंध में गोविंद इनानी ने बताया कि अगर इस प्लॉस्टिक कचरे को फैलाने वालों पर सख्त कार्यवाही कर इन्हें नहीं रोका गया तो हमे भविष्य में पर्यावरण संबंधी ख़तरों को झेलना पड़ेगा। इसके साथ ही नदी पर बने घाटों की सुध ली जाकर उनकी मरम्मत की जाये और साफ़ सफ़ाई की व्यवस्था की जाये। इस कड़ी में युवाओं ने शहरवासियो से आव्हान किया की वह आगे आकर कड़े कदम उठाकर नदी की साफ़ सफ़ाई में अपना योगदान दे।

# सेना के हेलिकॉप्टर ने जानबूझकर यात्री प्लेन को मारी टक्कर, कोई नहीं बचा ? ट्रंप ने दुर्घटना पर जताया संदेह

अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के पास एक भयानक हवाई दुर्घटना ने सभी को हिलाकर रख दिया है। अमेरिकी सेना के ब्लैकहॉक हेलिकॉप्टर और अमेरिकन एयरलाइंस के यात्री विमान के बीच टक्कर का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस हादसे को लेकर कई षड्यंत्रकारी थ्योरी (कॉन्सपिरेसी थ्योरी) सामने आ रही हैं। यहां तक कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस दुर्घटना को लेकर संदेह जताया है। यह हादसा अमेरिकी ट्रंप द्वारा मंगलवार को होमलैंड सुरक्षा विभाग में फेरबदल करने के कुछ दिनों बाद हुआ है, जिसमें परिवहन सुरक्षा प्रशासन और तटरक्षक बल के प्रमुखों को उनके कार्यकाल पूरा होने से पहले ही हटा दिया गया और एयर ट्रैफ़िक नियंत्रकों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई थी। 22 जनवरी की एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण विमानन सुरक्षा सलाहकार समूह के सभी सदस्यों को भी भंग कर दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हादसे पर संदेह जताते हुए सोशल मीडिया पर लिखाः विमान एक तय रूट पर रनवे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से हेलिकॉप्टर ने सीधा प्लेन की ओर उड़ान भरी। आसमान साफ था, प्लेन की लाइट्स ऑन थीं, फिर भी हेलिकॉप्टर ने रास्ता क्यों नहीं बदला? कंट्रोल टावर ने पायलट को जानकारी क्यों नहीं दी कि सामने प्लेन है? यह घटना रोकी जा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ यह सही नहीं है! यह घटना रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास हुई, जहां अमेरिकी सेना का ब्लैकहॉक हेलिकॉप्टर पीछे से एक अमेरिकन एयरलाइंस के विमान से टकरा गया। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों ही एयरक्राफ्ट पोमैक नदी में जा गिरे। एयरलाइन कंपनी ने पुष्टि की है कि विमान में कुल 64 लोग (चार क्रू मेंबर्स सहित) सवार थे, जबकि हेलिकॉप्टर में तीन सैन्य कर्मी मौजूद थे। अभी तक किसी को भी बचायानहीं जा सका है। दुर्घटना थी या आंतकी साजिश? घटना के बाद सोशल मीडिया पर लोग सवाल उठा रहे हैं- क्या यह महज एक हादसा था, या फिर सेना का हेलिकॉप्टर जानबूझकर प्लेन से टकराया? क्या यह कोई आतंकी साजिश हो सकती है? एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने चेतावनी क्यों नहीं दी? हेलिकॉप्टर पायलट ने आखिरी वक्त में बचने की कोशिश क्यों नहीं की? अब तक कितने शव बरामद हुए? जांच शुरू, कई सवालों के जवाब बाकी रिपोर्ट्स के मुताबिक, अब तक नदी से 19 शव निकाले जा चुके हैं और बचाव कार्य जारी है। अधिकारियों का मानना है कि मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि अभी कई लोग लापता हैं। हादसे के वक्त विमान में 64 यात्री और हेलिकॉप्टर में तीन सैन्य कर्मी मौजूद थे। अमेरिकी नागरिक उड्डयन प्रशासन और राष्ट्रीय परिवहन सुरक्षा बोर्ड ने घटना की जांच शुरू कर दी है। अमेरिकी सेना भी यह पता लगाने में जुटी है कि क्या यह महज एक एक्सीडेंट था या कोई बड़ी साजिश रडार रिकॉर्डिंग और एयर ट्रैफिक कंट्रोल कम्युनिकेशन की समीक्षा की जा रही है ताकि घटना के सही कारणों का पता लगाया जा सके। एविएशन विशेषज्ञों का कहना है कि सैन्य और व्यावसायिक उड़ानों के लिए अलग-अलग एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम होते हैं, जिससे ऐसी टक्कर होने की संभावना बेहद कम होती है। क्या यह ट्रैफिक कंट्रोल की बड़ी चूक थी? या फिर वाकई इसमें कोई गहरी साजिश छिपी है? अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में हुआ यह हादसा केवल एक दुर्घटना था या इसके पीछे कोई साजिश थी ,यह जांच के बाद ही स्पष्ट होगा। लेकिन ट्रंप के बयान और सोशल मीडिया पर उठ रहे सवालों ने इस घटना को और भी रहस्यमयी बना दिया है। अब सभी की नजरें अमेरिकी एजेंसियों की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो इस घटना का असली सच सामने लाएगी।

# युद्ध से तबाह गाजा को फिर बसाने में लगेंगे अरबों डॉलर, भारत कितनी मदद करेगा?

इजरायल-हमास युद्ध ने गाजा को खंडहर में बदल दिया है। उत्तरी गाजा में इमारतों का मलबा चारों ओर फैला हुआ है, सड़कें तबाह हो चुकी हैं, और बिजली-पानी की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। इस तबाह शहर को फिर से बसाने में अरबों डॉलर की जरूरत होगी। युद्धविराम के बाद जब लोग अपने घरों की ओर लौटे, तो वे अपने शहर को पहचान भी नहीं पाए। जहां कभी घर, बाजार और स्कूल हुआ करते थे, वहां अब सिर्फ मलबे के ढेर हैं। इजरायली बमबारी और जमीनी हमलों ने गाजा के कई कस्बों और गांवों को पूरी तरह मिटा दिया है। सड़कें और इन्फ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह नष्ट स्कूल और अस्पताल बुरी तरह क्षतिग्रस्त बिजली और पानी की आपूर्ति लगभग ठप पुनर्निर्माण की चुनौती गाजा के लोगों के लिए सबसे बड़ी चिंता यह है कि पुनर्निर्माण कब और कैसे होगा। इजरायल और हमास के बीच हुए युद्धविराम समझौते में इस बात का कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि युद्ध के बाद गाजा का प्रशासन कौन संभालेगा। 2007 से गाजा पर हमास का नियंत्रण है, जिसके कारण इजरायल और मिस्र ने इस क्षेत्र पर कड़ी नाकाबंदी लगा रखी है। इस नाकाबंदी के कारण निर्माण सामग्री और मानवीय सहायता गाजा तक पहुंचने में मुश्किलें आती हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि अगर नाकाबंदी जारी रहती है तो गाजा के पुनर्निर्माण में 350 साल तक लग सकते हैं। गाजा को कितना नुकसान हुआ? संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, युद्ध से गाजा को भारी नुकसान हुआ हैः - 245,000 से अधिक घर नष्ट हो गए हैं - 68 सड़क नेटवर्क पूरी तरह क्षतिग्रस्त - गाजा की 69% संरचनाएं नष्ट या क्षतिग्रस्त - 18 लाख से अधिक लोग बेघर - जल आपूर्ति का केवल 25% हिस्सा चालू आर्थिक नुकसान विश्व बैंक का अनुमान है कि युद्ध के कारण गाजा को 18.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है, जो 2022 में वेस्ट बैंक और गाजा के संयुक्त आर्थिक उत्पादन के बराबर है। मलबा हटाने में ही लगेंगे 21 साल । संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, गाजा में 50 मिलियन टन (5 करोड़ टन) से अधिक मलबा पड़ा हुआ है। - मलबा हटाने में 1.2 अरब डॉलर का खर्च आएगा । - अगर 100 से अधिक ट्रक बिना रुके काम करें, तो भी सफाई में 15 साल लगेंगे । - मलबे में 10,000 से अधिक शव दबे होने की आशंका । नाकाबंदी बनी सबसे बड़ी बाधा इजरायल का कहना है कि अगर नाकाबंदी हटाई गई तो हमास फिर से अपनी सैन्य ताकत बढ़ा सकता है। इजरायल को डर है कि हमास सीमेंट और धातु के पाइप का इस्तेमाल सुरंगें और रॉकेट बनाने में कर सकता है। भारत पहले भी फिलिस्तीनी क्षेत्रों में मानवीय सहायता भेजता रहा है। हालांकि, इस बार भारत की ओर से किसी ठोस सहायता की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन यह तय है कि अंतरराष्ट्रीय सहयोग के बिना गाजा का पुनर्निर्माण असंभव होगा। गाजा का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय इस तबाही के बाद कितनी मदद करता है और इजरायल-हमास संघर्ष का राजनीतिक समाधान कैसे निकलता है।

# शहरी नियोजन की विफलता और प्रदूषण जीबीएस के बढ़ते मामलों के लिए जिम्मेदार, सुप्रिया सुले का दावा

महाराष्ट्र के पुणे और उसके आस-पास के इलाकों में गिलियन-बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) के बढ़ते ममले राज्य सरकार के लिए चिंता का विषय है। इसी बीच शरद पवार गुट की एनसीपी नेता और सांसद सुप्रिया सुले ने जीबीएस के बढ़ते मामले के लिए पुणे नगर निगम की विफलता पर जोर देते हुए प्रशासन की आलोचना की। बता दें कि जीबीएस एक दुर्लभ बीमारी के तौर पर सामने आई है, जो अचानक सुन्नता, मांसपेशियों की कमजोरी और अंगों में गंभीर कमजोरी जैसी समस्याएं पैदा करती है। उन्होंने कहा कि शहर में गिलियन-बैरे सिंड्रोम (जीबीएस) के बढ़ते मामलों के लिए शहरी नियोजन की विफलता और बढ़ते प्रदूषण जिम्मेदार है। साथ ही सुले ने जीबीएस को एक दुर्लभ बीमारी बताते हुए इसके फैलने के पीछे वैज्ञानिक कारणों का पता लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया। बता दें कि बुधवार तक राज्य में 127 संदिग्ध जीबीएस के मरीज पाए गए हैं। वहीं पुणे में एक 56 वर्षीय महिला और सोलापुर में एक 40 वर्षीय व्यक्ति की जीबीएस से मौत भी हो गई है। सुले ने फडणनवीस सरकार से की मांग लोकसभा सदस्य सुले ने महाराष्ट्र सरकार से जीबीएस के मरीजों का सारा चिकित्सा खर्च सरकार देने की मांग की। उन्होंने यह भी कहा कि निराधार प्रबंधन के कारण यह बीमारी फैल रही है। सुप्रिया सुले ने आगे कहा कि इस समस्या को लेकर वे पुणे नगर निगम और राज्य सरकार को पत्र लिखेंगी। उन्होंने कहा कि जीबीएस का फैलाव शहरी नियोजन की विफलता का परिणाम है और प्रदूषण के कारण बीमारियों में वृद्धि हो रही है, इसलिए तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है। साथ ही सुले ने नगर निगम द्वारा बुनियादी ढांचे की कमी के बावजूद नई इमारतों और परियोजनाओं को मंजूरी दिए जाने की भी आलोचना की। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के पुणे जिले में बारामती का प्रतिनिधित्व करने वाली सांसद सुले पुणे के सिंहगढ़ रोड क्षेत्र के नांदेड़ गांव स्थित एक कुएं का दौरा करने गईं, जहां से दूषित पानी की आपूर्ति होने का संदेह जताया जा रहा है। साथ ही इसी दूषित जल को जीबीएस के मामलों में वृद्धि का कारण भी बताया जा रहा है। राज्य सरकार की ध्यान देने की मांग एनसीपी (एसपी) के कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले ने आगे कहा कि जीबीएस के बढ़ते मामलों के पीछे वैज्ञानिक कारणों का पता लगाने के लिए विशेषज्ञों से परामर्श करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि नदियां और बांध प्रदूषित हो रहे हैं और सरकार को इन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए। सरकार के सहयोग के लिए तैयार साथ ही सुले ने यह भी कहा कि हालांकि हम विपक्ष में हैं, लेकिन हम इन मुद्दों पर सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यह आरोप लगाया कि आम लोगों को सिर्फ सरकार की निराधार नीतियों के कारण परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

## नाबालिग से यौन उत्पीड़न के आरोप में आरोपी को तीन साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया

महाराष्ट्र के ठाणे में एक अदालत ने 2019 में एक लड़की का यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 51 वर्षीय व्यक्ति को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। पॉक्सो अदालत के न्यायाधीश डीएस देशमुख ने कहा कि ऐसी घटनाओं की जानकारी पुलिस को दी जानी चाहिए। इससे समाज में जागरूकता पैदा होती है और सजा आरोपियों के लिए निवारक के रूप में काम करेगी। विशेष लोक अभियोजक संध्या एच. मात्रे ने अदालत को बताया कि पांच जुलाई 2019 को पीड़िता 13 साल की थी और वह स्कूल जा रही थी, तब आरोपी मोइज हातिम रामपुरवाला ने उसका पीछा किया और उसे गलत तरीके से छुआ। लड़की ने आरोपी की हरकतों का विरोध किया। शोर मचाया और छाते से उसे मारने की कोशिश की। वहां से गुजर रही एक महिला ने पीड़िता को बचाया, जबकि आरोपी मौके से फरार हो गया। पीड़िता और महिला ने आरोपी का उसके घर तक पीछा किया और उसे पकड़ लिया। पीड़ित लड़की और महिला ने बाद में पुलिस से संपर्क किया और आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। न्यायाधीश देशमुख ने बुधवार को आरोपी को दोषी ठहराया। उन्होंने कहा कि इन दिनों नाबालिगों के साथ यौन उत्पीड़न के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इन घटनाओं के बाद बहुत कम ही पीड़ित शिकायत दर्ज कराने आते हैं। न्यायाधीश ने कहा, समाज को यह समझना चाहिए कि यह एक अपराध है और ऐसी घटनाओं की शिकायत की जानी चाहिए।

# गुजरात की झांकी ने लगाई हैट्रिक, पॉपुलर चॉइस में जनता के सर्वाधिक वोट हासिल किए

76वें गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय परेड में नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर प्रस्तुत की गई गुजरात की झांकी को 'पॉपुलर चॉइस' श्रेणी में सर्वाधिक वोट प्राप्त हुए हैं। गुजरात की झांकी 'गुजरात= आनर्तपुर से एकता नगर तक - विरासत से विकास का अद्भुत संगम' को 'पॉपुलर चॉइस' ने लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान प्राप्त कर जीत की हैट्रिक लगाई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुजरात की झांकी को पिछले तीन वर्षों से पॉपुलर चॉइस श्रेणी में प्रथम स्थान मिलने की गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए गुजरात के सभी नागरिकों को हार्दिक बधाई दी और आभार व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि प्रधानमंत्री के मंत्र 'विकास भी, विरासत भी' को गुजरात जनभागीदारी के जरिए साकार कर रहा है और भविष्य में भी अग्रणी रहेगा। उल्लेखनीय है कि 76वें गणतंत्र पर्व की राष्ट्रीय परेड में नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर विभिन्न राज्यों और सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की 31 झांकियां प्रस्तुत की गई थीं। गुजरात राज्य के सूचना विभाग की ओर से प्रस्तुत की गई झांकी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में गुजरात के आधुनिक विकास की गाथा को प्राचीन विरासत के साथ प्रस्तुत किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से अपनाए गए अभिनव और पारदर्शी दृष्टिकोण के अंतर्गत नागरिक इस परेड में प्रस्तुत की जाने वाली विभिन्न झांकियों के लिए अपने वोट ऑनलाइन माध्यम से देकर 'पॉपुलर चॉइस' श्रेणी की सर्वोत्तम झांकी का चयन कर सकते हैं। गुजरात सरकार के सूचना विभाग द्वारा इस परेड में प्रस्तुत की गई झांकी- 'गुजरात = आनर्तपुर से एकता नगर तक - विरासत से विकास का अद्भुत संगम' को जनता ने सबसे अधिक वोट दिए हैं। बड़ी संख्या में वोटिंग के साथ गुजरात की झांकी पॉपुलर चॉइस श्रेणी में लगातार तीसरे वर्ष प्रथम स्थान पर रही है। गुजरात की झांकी ने पॉपुलर चॉइस श्रेणी अवॉर्ड में अव्वल रहने की परंपरा 2023 के 74वें गणतंत्र दिवस परेड से शुरू की है। उस परेड में राज्य सरकार ने 'क्लीन-ग्रीन एनर्जी युक्त गुजरात' की थीम पर आधारित झांकी में प्रधानमंत्री के नवीकरणीय ऊर्जा के अधिकतम उपयोग के आह्वान को साकार करने में गुजरात की पहल को प्रस्तुत किया गया था। गत वर्ष यानी 2024 के 75 गणतंत्र पर्व की राष्ट्रीय परेड में गुजरात द्वारा प्रस्तुत 'धोरडो, वर्ल्ड बेस्ट टूरिज्म विलेज- UNWTOO विषय पर आधारित झांकी को भी पॉपुलर चॉइस श्रेणी में पहला स्थान मिला था। इतना ही नहीं, सर्वश्रेष्ठ झांकी के लिए निर्णायकों के पैनल-जूरी की चॉइस में भी गुजरात की इस झांकी ने 2024 में दूसरा स्थान प्राप्त किया था। इसी परंपरा में एक और उपलब्धि हासिल करते हुए गुजरात की झांकी ने 76वें गणतंत्र दिवस की राष्ट्रीय परेड में लगातार तीसरी बार प्रथम स्थान हासिल कर हैट्रिक लगाने का गौरव प्राप्त किया है।

# तिरुवनंतपुरम में घंटों लापता रहने के बाद कुएं से मिला बच्ची का शव कोच्चि में दो बांग्लादेशी गिरफ्तार

केरल के तिरुवनंतपुरम में दो साल की बच्ची की मौत पर रहस्य छाया हुआ है। बच्ची लापता होने के कुछ घंटों बाद अपने ही घर के पास कुएं में डूबी हुई पाई गई। पुलिस के अनुसार, सुबह से बच्ची को गायब देखकर माता-पिता ने पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई। जांच के दौरान बच्ची का शव घर के पास वाले कुएं से मिला। पुलिस ने बताया कि अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि बच्ची कुएं में कैसे गिरी, क्योंकि कुएं के आसपास दीवार है। परिवार वालों से पूछताछ की जा रही है। अग्निशमन और बचाव कर्मियों ने बच्ची के शव को कुएं से बाहर निकाला।

अवैध रूप में भारत में रहने के आरोप में कोच्चि से दो बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। उनकी पहचान 22 वर्षीय कोबीतिबा और 19 वर्षीय रूबीना शेख के तौर पर की गई है। दोनों को एर्नाकुलम ग्रामीण पुलिस सीमा के कोडानाडु से गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि दोनों ने पहले पश्चिम बंगाल की सीमा पार की और फिर बंगलूरू की यात्रा की। यहां से उन्होंने एजेंट की मदद से फर्जी आधार कार्ड हासिल किया। दोनों बांग्लादेशी महिलाओं को अदालत के समक्ष पेश किया गया और फिर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

दो सप्ताह पहले 28 वर्षीय थसलीमा बेगम की गिरफ्तारी के बाद एर्नाकुलम ग्रामीण जिला पुलिस प्रमुख वैभव सक्सेना ने एक विशेष अभियान ऑपरेशन क्लीन चलाया। इसी अभियान के तहत दोनों बांग्लादेशी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने बताया कि इन गिरफ्तारियों के साथ इस महीने ग्रामीण जिला पुलिस सीमा में हिरासत में लिए गए बांग्लादेशियों की संख्या बढ़कर सात हो गई है। इन गिरफ्तारियों के बाद पुलिस ने अवैध तरीके से सीमा पार कर फर्जी दस्तावेज हासिल करवाने वाले एजेंटों का पता लगाने के लिए पश्चिम बंगाल तक अपनी जांच का विस्तार करने का निर्णय लिया।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक श्रीमती ज्योती मिश्रा द्वारा कॉम्पेक प्रिंटर्स प्रा. लि. फ्री प्रेस हाउस 3/54, प्रेस कॉम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 45ए गुप्ता चैम्बर पहली मंजिल जावरा कंपाउंड इंदौर, (म.प्र.) से प्रकाशित।
प्रधान सम्पादक : अशीष मिश्रा आर.एन.आई. पंजीयन क्रमांक : एमपी/एच/आइएन 2009/34385 फोन नं : 0 ।31-4202569 फैक्स नं : 0731-4202569